गूंज सिंगरौली की

संपादक लाले विश्वकर्मा 6261729146 | www. goonjsingraulikee.in | goonjsingrauliki@gmail.com

वर्ष: 1 | अंक: 12 | सिंगरौली, सोमवार 2 मार्च 2026 | पृष्ठ: 8 | मूल्य: 2 रुपए | PRGI MPHIN/26/A0876

सिंगरौली-सीधी कोल ब्लॉक आवंटन पर NGT सख्ती, केंद्र-राज्य और अडानी समूह को नोटिस

एलिफेंट कॉरिडोर अधिसूचना में देरी पर भी मांगा जवाब, 22 अप्रैल को अगली सुनवाई

गूंज सिंगरौली की पत्रिका राम लखन पाठक

सीधी-सिंगरौली के घने वन क्षेत्र में कोयला ब्लॉक आवंटन और पर्यावरणीय स्वीकृति को लेकर एक महत्वपूर्ण कानूनी घटनाक्रम सामने आया है। (National Green Tribunal) की प्रधान पीठ, नई दिल्ली ने केंद्र सरकार, मध्यप्रदेश शासन, (Adani Group ìíæ National Board for Wildlife) को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। मामला पर्यावरणविद् अजय दुबे द्वारा दायर याचिका से संबंधित है, जिसमें मई 2025 में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता को चुनौती दी गई है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि सिंगरौली के लगभग 1500 हेक्टेयर अत्यंत घने और समृद्ध वन क्षेत्र को कोयला खनन हेतु आवंटित करते समय स्थापित पर्यावरणीय नियमों और वन्यजीव संरक्षण संबंधी प्रावधानों की अनदेखी की गई। प्रधान पीठ के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव एवं न्यायमूर्ति अफरोज अहमद की युगल पीठ ने सुनवाई के दौरान यह भी स्पष्ट किया कि पूर्व में उच्च न्यायालयों एवं एनजीटी के आदेशों के बावजूद सीधी-सिंगरौली क्षेत्र को अब तक (एलिफेंट कॉरिडोर) के रूप में अधिसूचित क्यों नहीं किया गया, इस पर भी संबंधित पक्षों से जवाब अपेक्षित है। न्यायाधिकरण ने मामले की अगली सुनवाई 22 अप्रैल 2026 को निर्धारित की है। याचिका में उल्लेख किया गया है कि वर्ष 2022 में केंद्र शासन द्वारा सिंगरौली क्षेत्र में अडानी समूह की कंपनियों महान कोल एनर्जी एवं स्ट्रेटाटेक मिनरल्स को लगभग 1500 हेक्टेयर वन भूमि कोयला उत्खनन के लिए आवंटित की गई थी। इसके उपरांत पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए केंद्र और राज्य स्तर पर आवेदन प्रस्तुत किया गया। आवेदन के परीक्षण हेतु गठित उच्चस्तरीय समिति ने अप्रैल 2024 में स्थल निरीक्षण के पश्चात अपनी रिपोर्ट में खनन गतिविधियों के विरुद्ध स्पष्ट अनुशंसा की थी। समिति ने अपने प्रतिवेदन में कहा था कि उक्त क्षेत्र अत्यंत समृद्ध जैव विविधता से परिपूर्ण है तथा इसके मध्य से प्रस्तावित (एलिफेंट कॉरिडोर) गुजरता है, जहां हाथियों की नियमित आवाजाही होती है। रिपोर्ट में यह भी इंगित किया गया था कि यदि क्षेत्र में कोयला उत्खनन प्रारंभ किया जाता है तो वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास को गंभीर क्षति पहुंचेगी और पर्यावरणीय संतुलन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। आरोप है कि समिति की इन अनुशंसाओं को दरकिनार करते हुए मई 2025 में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान कर दी गई और स्वीकृति आदेश में समिति की आपत्तियों का समुचित उल्लेख नहीं किया गया। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सिद्धार्थ राधेलाल गुप्ता ने न्यायाधिकरण के समक्ष तर्क रखा कि स्वयं केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा में शपथपत्र के माध्यम से यह जानकारी दी गई थी कि सीधी-सिंगरौली का विस्तृत वन क्षेत्र 'एलिफेंट कॉरिडोर' के रूप में अधिसूचित किए जाने हेतु प्रस्तावित है, किंतु आज तक इस संबंध में कोई औपचारिक अधिसूचना जारी नहीं की गई। उन्होंने यह भी कहा कि जिस क्षेत्र को अधिसूचना के दायरे में लाया जाना प्रस्तावित है, उसी के निकटवर्ती क्षेत्र को खनन हेतु निजी कंपनी को आवंटित कर दिया गया, जो वन्यजीव संरक्षण के सिद्धांतों के विपरीत है। मामले ने तब और तूल पकड़ा जब क्षेत्र में पेड़ों की कटाई प्रारंभ होने की सूचनाएं सामने आईं। इसके बाद पर्यावरणविद् अजय दुबे ने

न्यायाधिकरण का दरवाजा खटखटाया। उल्लेखनीय है कि पूर्व में भी इसी वन क्षेत्र को कोयला ब्लॉक के रूप में आवंटित किए जाने को लेकर स्थानीय नागरिकों और सामाजिक संगठनों द्वारा विरोध दर्ज कराया गया था। न्यायाधिकरण द्वारा केंद्र सरकार, राज्य सरकार, अडानी समूह तथा नेशनल वाइल्डलाइफ बोर्ड को नोटिस जारी किए जाने के बाद अब सभी पक्षों को चार सप्ताह के भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत करना होगा। आगामी सुनवाई 22 अप्रैल 2026 को होगी, जिसमें पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता, वन्यजीव संरक्षण तथा (एलिफेंट कॉरिडोर) की अधिसूचना से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विस्तृत सुनवाई होने की संभावना है। सिंगरौली-सीधी के वन क्षेत्र में औद्योगिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन का यह मामला अब व्यापक सार्वजनिक विमर्श का विषय बन गया है और इसकी दिशा आने वाले समय में क्षेत्रीय पर्यावरणीय नीति पर दूरगामी प्रभाव डाल सकती है।

कलेक्टर ने 2 मार्च को घोषित स्थानीय अवकाश को निरस्त कर 4 मार्च को अवकाश किया घोषित

गूंज सिंगरौली की पत्रिका

सिंगरौली। होली 2026 के मद्देनजर कलेक्टर गौरव बैनल ने 2 मार्च (सोमवार) को पहले घोषित स्थानीय अवकाश को निरस्त करते हुए अब 4 मार्च (बुधवार) को अवकाश घोषित किया है। यह बदलाव मुख्य रूप से 3 और 4 मार्च को होली के त्योहार को ध्यान में रखते हुए स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार किया गया है। विदित हो कि पूर्व में कलेक्टर द्वारा 2 मार्च 2026 सोमवार को होली (होलिका दहन) त्यौहार पर स्थानीय अवकाश घोषित किया गया था। शासन द्वारा होली के उपलक्ष्य में दिनांक 3 मार्च 2026 को पूर्व से सामान्य अवकाश घोषित है। क्षेत्र से प्राप्त हो रही जानकारी अनुसार यह ज्ञात होता है कि लोगों द्वारा दिनांक 3 मार्च के साथ-साथ 4 मार्च 2026 को भी होली खेलने का त्यौहार मनाया जायेगा। अतः पूर्व में जारी आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए पूर्व निर्धारित 2 मार्च 2026 के स्थानीय अवकाश को निरस्त कर दिनांक 4 मार्च 2026 बुधवार को जिला सिंगरौली सीमा क्षेत्रान्तर्गत स्थानीय अवकाश

महिला को प्रताड़ित कर आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाला आरोपी गिरफ्तार

गूंज सिंगरौली की पत्रिका

सिंगरौली। एनसीएल कॉलोनी निगाही स्थित एमक्यू-433 क्वार्टर में महिला की आत्महत्या के मामले में थाना नवानगर पुलिस ने मारपीट एवं प्रताड़ना कर आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार 27 फरवरी 2026 को मर्ग क्रमांक 06/2026 धारा 194 बीएनएसएस के तहत दर्ज प्रकरण की विवेचना के दौरान घटनास्थल का निरीक्षण, पंचनामा एवं साक्ष्य संकलन किया गया। गवाहों के बयान दर्ज करने और परिस्थिति जन्य साक्ष्यों के आधार पर मामला आत्महत्या के लिए उकसाने का पाया गया।

जांच में क्या सामने आया ?

मृतका फूलमती बसोर (35 वर्ष) निवासी दसौती, थाना नवानगर, निगाही परियोजना में ठेकेदारी कार्य से जुड़े संदीप बत्तूला के पास काम करती थी। जांच में सामने आया कि आरोपी द्वारा मृतिका के साथ लगातार मारपीट एवं मानसिक प्रताड़ना की जा रही थी। 26 फरवरी 2026 को आरोपी कथित रूप से महिला को जबरन मोटरसाइकिल से अपने निवास एमक्यू-433, सेक्टर-06, एनसीएल कॉलोनी निगाही ले गया। आरोप है कि लगातार प्रताड़ना से परेशान होकर महिला ने देर रात लगभग 12꞉30 बजे आरोपी के निवास के दूसरे कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।

आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में

जांच के आधार पर आरोपी संदीप बत्तूला (39 वर्ष) के विरुद्ध धारा 108 बीएनएस के तहत अपराध क्रमांक 0034/2026 पंजीबद्ध कर उसे विधिवत गिरफ्तार किया गया। चिकित्सीय परीक्षण के बाद आरोपी को न्यायालय बैढ़न में प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जिला जेल भेज दिया गया है। यह कार्रवाई

पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सर्वप्रिय सिन्हा के मार्गदर्शन तथा सीएसपी विन्ध्यनगर राहुल कुमार सैयाम के नेतृत्व में थाना प्रभारी नवानगर डॉ. अनिल कुमार पटेल एवं उनकी टीम द्वारा की गई। पुलिस ने बताया कि मामले की विवेचना जारी है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने जलालपुर पहुँचकर विधायक श्री लोधी की माताजी के निधन पर शोक संवेदनाएं व्यक्त कीं

भोपाल

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने रविवार को ग्वालियर जिले के ग्राम जलालपुर पहुँचकर विधायक श्री प्रीतम लोधी की माताजी स्व. श्रीमती भागवती बाई के निधन पर शोक संवेदनाएँ व्यक्त कीं। उन्होंने दिवंगत स्व. भागवती जी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि प्रदान की। इस अवसर पर वरिष्ठ विधायक एवं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री हेमंत खंडेलवाल, श्री जयप्रकाश राजौरिया, श्री प्रेमसिंह राजपूत सहित जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। विधायक श्री प्रीतम लोधी की माताजी श्रीमती भागवती बाई का गत 26 फरवरी को लगभग 100 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया था।

साईं डायग्नोस्टिक में सुविधाओं में कोसो दूर, लेकिन मरीजों के परिजनों के लिए बुनियादी इंतजाम तक नहीं

गूंज सिंगरौली की पत्रिका

सिंगरौली जिले में स्थित साईं डायग्नोस्टिक सेंटर एक बार फिर अव्यवस्थाओं को लेकर चर्चा में है। मरीजों ने बताया कि अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन और एक्स-रे जैसी जांच सुविधाओं के नाम पर मरीजों से मनमानी और मोटी रकम वसूली जा रही है, लेकिन इसके बावजूद मरीजों और उनके परिजनों के लिए मूलभूत सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं हैं। बताया जा रहा है कि सेंटर में जांच कराने आने वाले मरीजों के साथ आए परिजनों के बैठने के लिए उचित व्यवस्था नहीं है। घंटों इंतजार करने के दौरान लोगों को बाहर या इधर-उधर खड़े रहने को मजबूर होना पड़ता है। वहीं वाहनों के लिए पार्किंग व्यवस्था भी पूरी तरह लचर बताई जा रही है, जिससे आसपास यातायात अव्यवस्थित होने की शिकायतें सामने आ रही हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब जांच के नाम पर भारी शुल्क लिया जा रहा है तो मरीजों की सुविधा और सुरक्षा की जिम्मेदारी भी संचालक की होनी चाहिए। लोगों ने स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन से मामले की जांच कर कार्रवाई की मांग उठाई है। अब सवाल यह है कि लगातार सामने आ रही शिकायतों के बावजूद संबंधित विभाग कब संज्ञान लेगा और जिम्मेदारों पर कार्रवाई होगी

शक्तिनगर में 12 ग्राम हेरोइन के साथ तस्कर गिरफ्तार

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब ?12 लाख, मोबाइल भी जब्त

गूंज सिंगरौली की पत्रिका कार्यालय

शक्तिनगर (सोनभद्र)। जनपद में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत शक्तिनगर पुलिस ने 12 ग्राम अवैध हेरोइन के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। बरामद मादक पदार्थ की अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत लगभग 12 लाख रुपये बताई जा रही है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के निर्देश पर अपर पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) अनिल कुमार एवं क्षेत्राधिकारी पिपरी के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष शक्तिनगर कमलनयन दूबे के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई।

मुखबिर की सूचना पर दबिश

पुलिस टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक युवक अवैध मादक पदार्थ के साथ क्षेत्र में घूम रहा है। सूचना के आधार पर कोहरौल पानी टंकी के पास घेराबंदी कर रात करीब 8꞉35 बजे करनगिरि (लगभग 20 वर्ष), निवासी पीडब्ल्यूडी मोड़, शक्तिनगर को गिरफ्तार किया गया। तलाशी में उसके पास से 12 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। साथ ही एक सैमसंग एंड्रॉयड मोबाइल फोन (कीमत लगभग ?10,000) भी जब्त किया गया। बरामदगी के आधार पर थाना शक्तिनगर में मु0अ0सं0-35/2026 धारा 8/21/27ए/29 एनडीपीएस

एक्ट के तहत मामला पंजीकृत किया गया है। आरोपी को न्यायालय में पेश कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

पूछताछ में बड़े नेटवर्क का खुलासा

प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह काफी समय से हेरोइन की बिक्री कर रहा है। उसने खुलासा किया कि 27 फरवरी को रॉबर्ट्सगंज निवासी आकाश सोनकर ने उसे हेरोइन उपलब्ध कराई थी। इसके अलावा वह पहले चिल्काडाड़ निवासी अकरम से भी मादक पदार्थ लेकर बेचता था। पुलिस के अनुसार आरोपी का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है और वह पहले एनडीपीएस एक्ट के मामले में जेल जा चुका है।

कार्रवाई में शामिल टीम

गिरफ्तारी टीम में थानाध्यक्ष कमलनयन दूबे, उपनिरीक्षक अजय कुमार श्रीवास्तव (चौकी प्रभारी बीना), उपनिरीक्षक रंजीत कुमार, हेड कांस्टेबल अशोक कुमार सिंह, माधवानंद सिंह, दिनेश भारती एवं कांस्टेबल अक्षय यादव शामिल रहे। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जनपद में मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध अभियान आगे भी सख्ती से जारी रहेगा।

होलिका दहन में उपले व गौकाष्ठ के उपयोग को बढ़ावा, कलेक्टर के निर्देश

गूंज सिंगरौली की पत्रिका कार्यालय

सिंगरौली। पर्यावरण संरक्षण और जल बचाव के उद्देश्य से कलेक्टर गौरव बैनल ने जिले के सभी एसडीएम, तहसीलदार, जनपद पंचायत सीईओ, थाना प्रभारी एवं नगरीय निकाय अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि होलिका दहन में लकड़ियों के स्थान पर गो-काष्ठ (गौकाष्ठ) और गोबर के उपलों के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाए। कलेक्टर ने प्रदेश शासन के निर्देशों का हवाला देते हुए कहा कि जनसहयोग और सामाजिक सहभागिता के माध्यम से प्रयास किए जाएं ताकि होलिका दहन पर्यावरण हितैषी तरीके से संपन्न हो। उन्होंने नागरिकों से प्राकृतिक एवं हर्बल रंगों से होली खेलने तथा भाईचारे और सौहार्द के साथ पर्व मनाने की अपील भी की।

नि:शुल्क पंजीयन और सम्मान की व्यवस्था

कलेक्टर ने निर्देश दिए कि ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में सार्वजनिक रूप से होलिका दहन करने वाली संस्थाओं का पंचायत, तहसील और

नगरीय निकाय स्तर पर नि:शुल्क पंजीयन किया जाए। उन्होंने कहा कि जो संस्थाएं पूर्ण रूप से उपलों एवं गौकाष्ठ का उपयोग करेंगी, उन्हें पर्यावरण संरक्षण में सहयोग के लिए जिला स्तरीय कार्यक्रम में प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। साथ ही ऐसी संस्थाओं एवं पदाधिकारियों को माननीय मुख्यमंत्री की ओर से पर्यावरण संरक्षण संबंधी प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया जाएगा।

पर्यावरण और सामाजिक सद्भाव का संदेश

राज्य शासन द्वारा इस वर्ष होली को पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक सद्भाव के संदेश के साथ मनाने का आह्वान किया गया है। इसी क्रम में सभी जिला कलेक्टरों को होलिका दहन में लकड़ी के स्थान पर उपलों और गौकाष्ठ के उपयोग को बढ़ावा देने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए इस पहल को सफल बनाएं।

आरडीएसएस के कार्यों का समय पर उपभोक्ताओं को मिले लाभ ˜ऊर्जा मंत्री श्री तोमर

भोपाल बिजली उपभोक्ताओं की सुविधाओं के लिए विद्युत कंपनी की टीम गंभीरता से कार्य करे। आरडीएसएस के नए कार्यों का समय पर उपभोक्ताओं को लाभ मिले, ताकि उपभोक्ता संतुष्टि में बढ़ोत्तरी हो। उपभोक्ता सुविधाओं से संबंधित कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने ये बातें रविवार को पोलोग्राउंड इंदौर स्थित पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के प्रबंध निदेशक कार्यालय में विभागीय योजनाओं की समीक्षा के दौरान कही उन्होंने कहा कि आरडीएसएस के सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए नए कार्य हो रहे हैं। यह कार्य गुणवत्ता से हो, समय से पूर्ण किए जाए। ताकि परियोजना का उद्देश्य समय पर पूरा हो। श्री तोमर ने कहा कि आरडीएसएस अंतर्गत जो ऐजेंसियों लापरवाही कर रही है, उन पर कठोर कार्रवाई की जाए। साथ ही अच्छा कार्य करने वाले एजेंसी को नियमानुसार अतिरिक्त कार्य दिया जा सकता है। श्री सिंह ने केपेसिटर बैंक की स्थापना के बाद उनका गुणवत्ता परीक्षण एवं उनसे हो रहे फायदे की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने एनएबीएल, एलटीएमटी लेब का सतत पर्यवेक्षण करने के निर्देश दिए। कंपनी के प्रबंध निदेश श्री अनूप कुमार सिंह ने कहा कि आरडीएसएस अंतर्गत 97 में से 87 ग्रिड का कार्य पूर्ण कर बिजली आपूर्ति शुरू की गई हैं। वहीं सात हजार सात सौ ट्रांसफार्मर लगाए जा चुके है। एलटी केबल कार्य, अंडर ग्राउंड केबल, ग्रिड रिनोवेशन व अन्य कार्य सतत पूर्ण होते जा रहे हैं।

बजट की आड़ में मुनाफाखोरों का खेल,तंबाकू उत्पादों की कालाबाजारी से उपभोगता बेहाल

संवाददाता

नरसिंहपुर। केंद्रीय बजट 2026 में तंबाकू उत्पादों पर टैक्स के नए नियमों की घोषणा क्या हुई, जिले के मुनाफाखोरों और जमाखोरों के लिए चांदी हो गई। टैक्स के नए ढांचे (40त्न त्नस्ञ्च और एक्साइज ड्यूटी) का हवाला देकर नरसिंहपुर शहर से लेकर ग्रामीण अंचलों तक बीड़ी और सिगरेट की कीमतों में आग लगा दी गई है। चौंकाने वाली बात यह है कि नया माल बाजार में आने से पहले ही पुराने स्टॉक को ऊंचे दामों पर बेचकर अवैध वसूली का खेल खुलेआम चल रहा है, जिस पर स्थानीय प्रशासन पूरी तरह मौन साधे बैठा है।

पुराना स्टॉक और मनमानी कीमतें

आम जनता से मिली शिकायतों के अनुसार, जिले के बाजारों में सरेआम लूट मची है। जो बीड़ी का बंडल महज कुछ दिन पहले 10 रूपये में उपलब्ध था, दुकानदार उसके लिए अब 12 से 15 रूपये तक वसूल रहे हैं। यही हाल सिगरेट का भी है, जहां 5 रूपये वाली सिगरेट 7 से 8 रूपये में बेची जा रही है। उपभोक्ताओं का आरोप है कि पैकेट पर पुरानी एमआरपी छपी होने के बावजूद दुकानदार उसे कम दाम पर देने को तैयार नहीं हैं। विरोध करने पर माल की कमी का बहाना बनाकर ग्राहकों को

बैरंग लौटा दिया जाता है।

जमाखोरी से पैदा की गई कृत्रिम किल्लत

सूत्रों की मानें तो बजट की घोषणा होते ही बड़े थोक व्यापारियों ने रातों-रात गोदामों से माल गायब कर दिया था। बाजार में जानबूझकर शॉर्टेज दिखाई गई ताकि बाद में मनमाने रेट पर माल निकाला जा सके। अब वही पुराना स्टॉक नई कीमतों के नाम पर कालाबाजारी के जरिए बाजार में उतारा जा रहा है। छोटे दुकानदार भी इस बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं और उनका तर्क है कि पीछे से ही उन्हें महंगा माल मिल रहा है।

प्रशासन की चुप्पी पर उठ रहे सवाल

इस पूरे घटनाक्रम ने खाद्य एवं औषधि प्रशासन और स्थानीय पुलिस की कार्यप्रणाली को कटघरे में खड़ा कर दिया है। एमआरपी से अधिक दाम वसूलना एक दंडनीय अपराध है, फिर भी अब तक मुनाफाखोरों पर कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई है। प्रशासनिक ढिलाई के कारण जमाखोरों के हौसले बुलंद हैं। नागरिकों का कहना है कि सरकार ने टैक्स स्वास्थ्य सुरक्षा के नाम पर बढ़ाया है, लेकिन धरातल पर इसका फायदा सिर्फ बिचौलियों और कालाबाजारी करने वालों को मिल रहा है, जबकि मध्यम और गरीब वर्ग की जेब पर डकैती डाली जा रही है।

विकसित भारत युवा संसद में गूँजी लोकतंत्र की आवाज, पूर्व सांसद ने युवाओं को दी संवैधानिक मूल्यों की सीख

संवाददाता

नरसिंहपुर। स्वामी विवेकानंद शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नरसिंहपुर में माय भारत एवं राष्ट्रीय सेवा योजना के संयुक्त तत्वावधान में जिला स्तरीय विकसित भारत युवा संसद 2026 का भव्य आयोजन संपन्न हुआ। इस गरिमामयी कार्यक्रम में जिले भर के युवाओं ने संसदीय प्रक्रियाओं को करीब से समझा और देश के लोकतांत्रिक भविष्य को लेकर अपनी प्रखर वैचारिक प्रस्तुति दी।

आपातकाल का स्मरण और लोकतांत्रिक मूल्य -

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व राज्यसभा सांसद कैलाश सोनी ने अपने ओजस्वी उद्बोधन में 25 जून 1975 के आपातकाल का विशेष रूप से स्मरण कराया। उन्होंने कहा कि आज से ठीक 50 वर्ष पूर्व लागू हुआ आपातकाल भारतीय लोकतंत्र का वह काला अध्याय है, जो हमें संवैधानिक मूल्यों और नागरिक स्वतंत्रता की असली अहमियत सिखाता है। उन्होंने युवाओं को सचेत करते हुए कहा कि एक जीवंत लोकतंत्र के लिए प्रेस की स्वतंत्रता और न्यायपालिका की स्वायत्तता अनिवार्य है। उन्होंने आह्वान किया कि लोकतंत्र की रक्षा करना हम सभी का सामूहिक कर्तव्य है।

युवाओं ने दिखाई नेतृत्व क्षमता -

इस जिला स्तरीय प्रतियोगिता के लिए माय भारत पोर्टल के माध्यम से कुल 75 प्रतिभागियों ने अपना पंजीकरण कराया था। कड़े मुकाबले के बाद 5 श्रेष्ठ वक्ताओं का चयन किया गया, जो आगामी राज्य स्तरीय युवा संसद प्रतियोगिता में जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस दौरान प्रोफेसर डॉ. सतीश दुबे ने भारतीय संविधान की धारा 352 और 1975 के आपातकाल के दौरान मीसा कानून के प्रभाव पर तकनीकी प्रकाश डाला। विशिष्ट अतिथि महंत प्रीतमपुरी ने छात्र संघ चुनावों की प्रासंगिकता और नेतृत्व विकास पर अपनी बात रखी।

गणमान्य जनों की उपस्थिति -

वरिष्ठ समाजसेवी इंजी. सुनील कोठारी ने छात्र-छात्राओं को मुख्य अतिथि के अनुभवों से प्रेरणा लेने हेतु प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम के अध्यक्ष नारायण श्रीवास्तव ने कैलाश सोनी के साथ बिताए युवावस्था के संस्मरण सुनाते हुए उन्हें किशोरावस्था से ही एक प्रखर वक्ता बताया। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. आर.बी. सिंह ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया।

सफल आयोजन में रही इनकी भूमिका -

कार्यक्रम का कुशल संचालन श्रीमती शिल्पी तिवारी द्वारा किया गया। आयोजन की सफलता में नोडल अधिकारी गजेंद्र कुमार सिंह और एनएसएस प्रभारी डॉ. अमित ताम्रकार की मुख्य भूमिका रही। निर्णायक मंडल में प्रो. सतीश दुबे, जय नारायण शर्मा, निलेश जाट, संजय तिवारी और अनुराधा नामदेव शामिल रहे। इस अवसर पर मार्गदर्शक समिति के सदस्य, गणमान्य नागरिक और बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

क्या षड्यंत्र के घेरे में शंकराचार्य ? झोतेश्वर में विलासिता के आरोपों की खुली पोल

शंकराचार्य के विरुद्ध साजिश के विरोध में गूँजा मौन आक्रोश,सड़कों पर उतरे हजारों भक्त

संवाददाता

झोतेश्वर/गोटेगांव। ज्योतिष्पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के विरुद्ध उत्तर प्रदेश में दर्ज किए गए मुकदमों और उन पर लगाए गए विलासिता के आरोपों ने समूचे नरसिंहपुर जिले में भारी आक्रोश पैदा कर दिया है। एक ओर जहां गोटेगांव की सड़कों पर हजारों भक्तों ने मौन रहकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, वहीं दूसरी ओर झोतेश्वर स्थित उनके निवास %त्रिपुरालय% की सादगी ने उन पर लगे आलीशान सुख-सुविधाओं के दावों को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है।

मौन जुलूस के जरिए गूँजा तीव्र आक्रोश

नगर में बोर्ड परीक्षाओं की संवेदनशीलता को देखते हुए प्रशासन ने विरोध प्रदर्शन के लिए लाउडस्पीकर की अनुमति नहीं दी थी। ऐसे में गुरु भक्तों ने मौन रहकर अपना विरोध दर्ज कराने का निर्णय लिया। श्री देव ठाकुर बाबा मंदिर परिसर से शुरू हुआ यह विशाल मौन जुलूस मुख्य बाजार, स्टेशन रोड और रिपटा होते हुए श्री ब्रह्मचारी राम मंदिर पहुँचा। जुलूस में शामिल भक्तों की आँखों में आक्रोश साफ दिखाई दे रहा था। इस प्रदर्शन की सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही कि इसमें किसी एक विचारधारा के नहीं, बल्कि सभी राजनीतिक दलों और समाज के हर वर्ग के

लोग शंकराचार्य के सम्मान में एक साथ नजर आए।

प्रयागराज विवाद और फर्जी एफआईआर का मामला

ब्रह्मचारी अचलानंद महाराज और भक्त मंडली ने स्पष्ट किया कि प्रयागराज के झूंसी थाने में स्वामी जी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और अन्य गंभीर धाराओं में दर्ज मुकदमा पूरी तरह राजनीति से प्रेरित और तथ्यहीन है। भक्तों का आरोप है कि जनवरी 2026 में माघ मेले के दौरान संगम स्नान से रोकने और पुलिस द्वारा की गई अभद्रता के विरोध में जब शंकराचार्य ने 11 दिनों तक धरना दिया, तभी से प्रशासन उनके पीछे पड़ा है। यह एफआईआर उसी विवाद का बदला लेने का एक तरीका है।

झोतेश्वर आश्रम की हकीकत- विलासिता नहीं, सादगी का संगम

हाल ही में मीडिया और सोशल मीडिया पर यह दावा किया गया था कि शंकराचार्य के पास पांच मंजिला शीश महल और स्विमिंग पूल जैसी लग्जरी सुविधाएं हैं। लेकिन जब झोतेश्वर के परमहंसी गंगा आश्रम स्थित त्रिपुरालय की पड़ताल की गई, तो वहां केवल एक साधारण दो मंजिला भवन मिला। निचले तल पर श्रद्धालुओं के बैठने की जगह है और ऊपरी मंजिल पर स्वामी जी के विश्राम के लिए एक सामान्य कक्ष बना है। यहां किसी भी प्रकार की लग्जरी सुविधा या आलीशान विलासिता का कोई प्रमाण नहीं मिला। आश्रम के संस्कृत विद्यालय के छात्रों ने भी इन आरोपों को उनके गुरु की छवि धूमिल करने वाला बताया।

गौसेवा की आवाज दबाने के लिए सनातन पर प्रहार

अचलानंद महाराज ने कहा कि जब से शंकराचार्य स्वामी जी ने गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने के लिए पदयात्रा और आंदोलन शुरू किया है, तब से वे कुछ शक्तियों की आँखों की किरकिरी बन गए हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यह हमला केवल एक व्यक्ति विशेष पर नहीं, बल्कि समूची सनातन गुरु परंपरा पर है। जबलपुर की पूर्व महापौर कल्याणी पांडे ने भी इन आरोपों को दुर्भावनापूर्ण बताया और गौशाला संचालन में स्वामी जी की सक्रिय भूमिका की सराहना की।

आगामी जन आंदोलन की चेतावनी

आश्रम प्रबंधन और शिष्य मंडली ने शासन-प्रशासन से मांग की है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच की जाए। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि यह मानसिक और प्रशासनिक उत्पीड़न बंद नहीं हुआ, तो आने वाले समय में देशभर के गुरु भक्त एक बड़ा जन आंदोलन छेड़ने के लिए विवश होंगे। फिलहाल गोटेगांव और झोतेश्वर क्षेत्र में स्थिति तनावपूर्ण लेकिन शांतिपूर्ण बनी हुई है।

नियमों को ताक पर रखकर काटी गई अवैध कॉलोनी पर प्रशासन का डंडा,कालोनाइजर को दी गई सख्त हिदायत

संवाददाता

तेंदूखेड़ा। तेंदूखेड़ा नगर के डोला मार्ग स्थित खेतों में अवैध रूप से प्लॉट काटकर बसाई गई कॉलोनी में मूलभूत सुविधाओं को ताक पर रखने का एक बड़ा मामला सामने आया है। कालोनाइजर द्वारा प्लॉट बेचते समय ग्राहकों को सुनहरे सपने दिखाए गए थे, जिसमें पक्की सड़क, व्यवस्थित नाली, जल निकासी, सुंदर गार्डन और पार्किंग जैसी सुविधाओं का वादा किया गया था। इन वादों के झांसे में आकर दर्जनों लोगों ने अपनी जीवन भर की पूंजी लगाकर यहां प्लॉट खरीदे और मकान बनाकर रहने लगे। लेकिन वर्षों बीत जाने के बाद भी कॉलोनी में विकास के नाम पर एक ईंट तक नहीं रखी गई, जिससे अब रहवासियों का धैर्य जवाब दे गया है। परेशान कॉलोनीवासियों ने सामूहिक रूप से प्रशासन के पास अपनी गुहार लगाई, जिसके बाद प्रशासनिक अमला हरकत में आया। अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और कालोनाइजर को कड़ी फटकार लगाते हुए जल्द से जल्द मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।

सुविधाओं के नाम पर मिला सिर्फ आश्वासन

डोला मार्ग पर स्थित कृषि भूमि को कालोनाइजर द्वारा छोटे-छोटे टुकड़ों में विभाजित कर अवैध रूप से बेच दिया गया। प्लॉट बेचते समय यह भरोसा दिलाया गया था कि यहां एक सर्वसुविधायुक्त व्यवस्थित कॉलोनी विकसित की जाएगी। वर्तमान स्थिति यह है कि कॉलोनी में न तो पक्की सड़कें बनी हैं और न ही जल निकासी का कोई मार्ग है। बारिश और घरों से निकलने वाला गंदा पानी खाली पड़े प्लॉटों में जमा हो रहा है, जिससे पूरी कॉलोनी में दलदल और गंदगी का माहौल बना हुआ है। सड़ांध और मच्छरों के बढ़ते प्रकोप के कारण यहां बीमारियों के फैलने का खतरा भी मंडराने लगा है।

पार्किंग और गार्डन की जगह सिर्फ खाली मैदान

कालोनाइजर ने विज्ञापन और प्रचार के दौरान बच्चों के खेलने के लिए गार्डन और वाहनों के लिए पार्किंग स्थल का दावा किया था। धरातल पर स्थिति इसके बिल्कुल उलट है। कॉलोनी में न तो बच्चों के लिए कोई पार्क विकसित किया गया है और न ही पार्किंग की जगह छोड़ी गई है। मजबूरन लोग अपने वाहन सड़कों के किनारे खड़े कर रहे हैं, जिससे आवागमन में परेशानी हो रही है और आए दिन छोटी-मोटी दुर्घटनाएं होती रहती हैं। निवासियों का कहना है कि स्वच्छता का अभाव और कचरे के ढेर अब यहां की पहचान बन गए हैं।

एसडीएम ने स्वयं मौके पर पहुंचकर लगाई फटकार

मामले की गंभीरता और नागरिकों की लगातार मिल रही शिकायतों को देखते हुए अनुविभागीय अधिकारी (एसडीएम) पूजा सोनी स्वयं निरीक्षण के लिए कॉलोनी पहुंचीं। निरीक्षण के दौरान कॉलोनी की बदहाल स्थिति देख वे दंग रह गईं। उन्होंने मौके पर मौजूद कालोनाइजर को जमकर फटकार लगाई और स्पष्ट किया कि जनता के साथ इस तरह का धोखा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एसडीएम ने निर्देश दिए कि कॉलोनी में तत्काल प्रभाव से सड़क निर्माण, नालियों की सफाई और जल निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए ताकि नागरिकों का जीवन सुगम हो सके।

अवैध कॉलोनियों के जाल से आक्रोशित जनता

स्थानीय नागरिकों में इस पूरे प्रकरण को लेकर भारी आक्रोश है। उनका कहना है कि उन्होंने इसे वैध कॉलोनी मानकर निवेश किया था, लेकिन अब उन्हें बुनियादी जरूरतों के लिए भी प्रशासन के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। नगर में कृषि भूमि को आवासीय बताकर बिना अनुमति के कॉलोनी काटने का चलन तेजी से बढ़ रहा है। रहवासियों ने मांग की है कि ऐसी अवैध कॉलोनियों को नियमित कर वहां सरकारी सुविधाएं दी जाएं और दोषी कालोनाइजरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। एसडीएम कार्यालय के अनुसार, इस कॉलोनी से संबंधित मामला पहले से ही प्रक्रिया में है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर विकास कार्य पूरे नहीं किए गए और कॉलोनी विकास की शर्तों का पालन नहीं हुआ, तो प्रशासन कुर्की और अन्य सख्त वैधानिक कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगा। इस कार्रवाई के बाद कॉलोनीवासियों में एक नई उम्मीद जगी है कि शायद अब उन्हें नारकीय जीवन से मुक्ति मिलेगी।

जेईई मेन्स परीक्षा में आशुतोष सिंह राजपूत ने लहराया सफलता का परचम

संवाददाता

गोटेगांव। श्री देव मुरलीधर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गोटेगांव के पूर्व छात्र आशुतोष सिंह राजपूत ने जेईई मेन्स 2026 की परीक्षा में 96.90 परसेंटाइल अंक प्राप्त कर विद्यालय और नगर का नाम रोशन किया है। आशुतोष विद्यालय की शिक्षिका श्रीमती राखी राजपूत एवं श्री विक्रम सिंह राजपूत के सुपुत्र हैं। उनकी इस उपलब्धि पर बाल शिक्षा समिति एवं श्री देव मुरलीधर विद्यालय परिवार ने उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए सफलता के लिए हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं।

सरदार सिंह पटेल ने एसआरजी ऑफिस में जनसंवाद कर जानीं क्षेत्रवासियों की समस्याएं

संवाददाता

गोटेगांव। गोटेगांव नगर की अग्रणी संस्था मणिनागेंद्र सिंह फाउंडेशन के सचिव सरदार सिंह पटेल ने एसआरजी ऑफिस में क्षेत्र के नागरिकों से सीधा संवाद कर उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना। साप्ताहिक रूप से प्रत्येक शुक्रवार को आयोजित होने वाले इस जनसंवाद कार्यक्रम में आपसी विवाद, सामाजिक समस्याएं, पेयजल आपूर्ति, जर्जर सड़कों की मरम्मत, बिजली बिलों में विसंगति और सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित रहने जैसे अनेक मामले सामने आए। सरदार सिंह पटेल ने मौके पर ही संबंधित विभाग के अधिकारियों से चर्चा कर शिकायतों का निश्चित समय सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण निराकरण करने के निर्देश दिए। जनसुनवाई में पहुंचे कई ग्रामीणों के छोटे-मोटे विवादों का मौके पर ही समाधान किया गया, जिससे उन्हें बड़ी राहत मिली। इस अवसर पर सचिव सरदार सिंह पटेल ने कहा कि यह कार्यक्रम जनता के विश्वास को मजबूत करने की दिशा में एक प्रभावी कदम है। कार्यक्रम में पूर्व विधायक हाकम सिंह चढ़ार, जिला भाजपा उपाध्यक्ष कुंवर हेमेंद्र सिंह सहित अन्य समाजसेवी व जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।

नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर बरसी गाज, पुलिस ने वसूला भारी जुर्माना

संवाददाता

नरसिंहपुर। जिले में सड़क सुरक्षा और ध्वनि प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस अधीक्षक डॉ. ऋषिकेश मीणा के निर्देशन में यातायात पुलिस ने विशेष चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले चार पहिया और दो पहिया वाहनों के खिलाफ सख्त चालानी कार्रवाई की गई। यह विशेष अभियान थाना प्रभारी ममता तिवारी और एएसआई सुरेश पटेल के नेतृत्व में चलाया गया। टीम ने शहर के मुख्य चौराहों पर घेराबंदी कर वाहनों की सघन चेकिंग की। चेकिंग के दौरान 4 बुलेट मोटरसाइकिलों को रोका गया, जिनमें कंपनी के साइलेंसर की जगह तेज आवाज करने वाले मॉडिफाइड साइलेंसर लगे थे। इन पर कुल 4,000 रूपये का जुर्माना लगाया गया। वहीं, नियमों के विरुद्ध चार पहिया वाहन के शीशों पर काली फिल्म लगाकर घूमने वाले चालक से भी 500 रूपये का समन शुल्क वसूला गया। थाना प्रभारी ममता तिवारी ने वाहन चालकों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि वाहनों में किसी भी प्रकार का अवैध मॉडिफिकेशन न कराएं। तेज आवाज वाले साइलेंसर से न केवल आम जनता को परेशानी होती है, बल्कि यह कानूनन अपराध भी है। पुलिस अधीक्षक के निर्देशों के तहत यह अभियान भविष्य में भी निरंतर जारी रहेगा।

होली की तारीखों को लेकर असमंजस खत्म, जानें होलिका दहन और रंगों के उत्सव का सटीक समय

संवाददाता

नरसिंहपुर। इस साल होली की तारीखों को लेकर आम जनमानस में बनी असमंजस की स्थिति पर विराम लग गया है। ज्योतिषाचार्य पंडित महेंद्र कृष्ण महाराज और पंचांग की गणना के अनुसार, ग्रह-नक्षत्रों और भद्रा की स्थिति के कारण इस बार त्योहार की तारीखें कुछ विशेष होंगी। शास्त्रीय नियमों के अनुसार, होलिका दहन हमेशा पूर्णिमा तिथि और रात्रि काल में ही किया जाता है। 2 मार्च 2026 को शाम 5ञ्18 बजे से पूर्णिमा तिथि शुरू हो जाएगी, जो 3 मार्च की शाम 4ञ्33 बजे तक रहेगी। चूंकि पूर्णिमा 2 मार्च की रात को विद्यमान है, इसलिए होलिका दहन इसी रात किया जाएगा। हालांकि, इस बार दहन पर भद्रा का साया रहेगा, जो 2 मार्च शाम 5ञ्18 से शुरू होकर 3 मार्च सुबह 4ञ्56 तक रहेगा। शास्त्रों में भद्रा के दौरान दहन वर्जित है, इसलिए %भद्रा पुच्छ% काल में रात 12ञ्50 बजे से रात 2ञ्02 बजे तक का समय दहन के लिए सर्वश्रेष्ठ और शुभ मुहूर्त रहेगा। विशेष बात यह है कि 3 मार्च को पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लग रहा है। भारत में दिखाई देने के कारण इसका सूतक काल मान्य होगा, जिसमें कोई भी मांगलिक कार्य या उत्सव मनाना वर्जित रहता है। इस कारण धुलेंडी यानी रंगों वाली होली 4 मार्च 2026, बुधवार को मनाई जाएगी। इसी दिन लोग एक-दूसरे को रंग-गुलाल लगाकर भाईचारे का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे।

सूखाखेरी में भक्ति की बयार - राम के आदर्शों को जीवन में उतारना ही सच्ची मानवता

संवाददाता

गाडरवारा। क्षेत्र के समीपी ग्राम सूखाखेरी में आयोजित 45वां श्री विष्णु महायज्ञ एवं मानस सम्मेलन अपने अंतिम दौर में पहुँच गया है। यज्ञ में प्रतिदिन बड़ी संख्या में धर्मप्रेमी श्रद्धालु यज्ञ शाला की परिक्रमा कर और विद्वानों के प्रवचन सुनकर पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। आज 28 फरवरी, शनिवार को पूर्ण आहुति एवं विशाल भंडारे के साथ इस आध्यात्मिक आयोजन का समापन होगा। प्रवचन कार्यक्रम में जगतगुरु कामदगिरी पीठाधीश्वर श्री रामस्वरूपाचार्य जी महाराज ने चित्रकूट धाम की महिमा बताते हुए कहा कि भगवान राम का चरित्र संपूर्ण मानवता के लिए प्रेरणा पुंज है। उन्होंने जटायु के बलिदान और हनुमान जी की अनन्य भक्ति का उदाहरण देते हुए समाज को धर्म के मार्ग पर चलने का आह्वान किया। वहीं, कथावाचक अंकुश जी महाराज ने महाभारत के प्रसंगों के माध्यम से वर्तमान पीढ़ी को सचेत किया। उन्होंने कहा कि आज कलयुग में धन-संपत्ति के मोह के कारण भाई-भाई के बीच दूरियां बढ़ रही हैं, जो चिंताजनक है। इस भव्य आयोजन को सफल बनाने में लोक कल्याण मंडल और समस्त ग्रामवासी पूरे मनोयोग से जुटे हुए हैं।

15-20 साल पुराने वाहनों पर भी नए के आधार पर टैक्स वसूली अन्याय गोलू सोनी

फाइनेंस रिकवरी में दबंगों के इस्तेमाल पर लगे अंकुश, सरकार से दो टूक मांग

बैतूल। मध्यप्रदेश में पुराने वाहनों की बिक्री पर परिवहन विभाग द्वारा वसूले जा रहे एक प्रतिशत ट्रांसफर टैक्स को लेकर विरोध तेज हो गया है। भारतीय वाहन खरीदी बिक्री विक्रेता संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष गोलू सोनी ने साफ कहा है कि अन्य राज्यों की तुलना में मध्यप्रदेश में यह अतिरिक्त बोझ वाहन खरीदारों और विक्रेताओं दोनों पर पड़ रहा है, जबकि छत्तीसगढ़ राज्य ने यह टैक्स समाप्त कर अपने नागरिकों को राहत दे दी है। गोलू सोनी ने कहा कि वर्तमान में पूरे भारत में यह व्यवस्था केवल मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में लागू थी, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने एक प्रतिशत टैक्स समाप्त कर दिया है। ऐसे में मध्यप्रदेश सरकार से अपेक्षा है कि वह भी पुराने वाहनों की बिक्री पर लगाया गया यह टैक्स खत्म कर आम आदमी को राहत दे। उन्होंने सवाल उठाया कि अनाप-शनाप टैक्स वसूली के बावजूद भी प्रदेश पर कर्ज का बोझ कम नहीं हो रहा है, फिर आम नागरिकों पर अतिरिक्त भार क्यों डाला जा रहा है। उन्होंने बताया कि स्थिति तब और गंभीर हो जाती है जब 15 से 20 वर्ष पुराने वाहन की बिक्री पर भी उसकी वर्तमान वास्तविक कीमत के बजाय नए वाहन की तुलना के आधार पर एक प्रतिशत टैक्स वसूला जाता है। इससे वाहन मालिक और खरीदार दोनों पर अनावश्यक आर्थिक दबाव बनता है। उनका कहना है कि यह व्यवस्था व्यावहारिक नहीं है और इसे तत्काल समाप्त किया जाना चाहिए। भारतीय वाहन खरीदी बिक्री विक्रेता संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष गोलू सोनी ने यह भी आरोप लगाया कि कई निजी फाइनेंस कंपनियां बकाया वसूली के लिए दबंग और गुंडा तत्वों का सहारा लेती हैं। ऐसे मामलों पर सरकार को सख्ती से अंकुश लगाना चाहिए ताकि वाहन मालिकों का उत्पीड़न न हो।

बैतूल में शराबखोरी के खिलाफ विभिन्न समाजों का निर्णायक मोर्चा

एसपी,कलेक्टर को सौंपा संयुक्त ज्ञापन

अवैध शराब निर्माण-विक्रय पर रोक नहीं लगी तो आंदोलन की चेतावनी

बैतूल। जिले के ग्रामीण और शहरी इलाकों में तेजी से बढ़ती शराबखोरी, अवैध मदिरा निर्माण और सार्वजनिक स्थलों पर खुलेआम शराब सेवन से बिगड़ती कानून-व्यवस्था को लेकर विभिन्न समाज संगठनों ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सर्व गोंड, गवली, कुनबी, कोरकू एवं मेहरा समाज संगठनों के पदाधिकारियों ने एकजुट होकर पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर को संयुक्त ज्ञापन सौंपते हुए तत्काल और कठोर कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि शराब के नशे में मारपीट, उपद्रव, गाली-गलौज, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार, घरेलू हिंसा तथा सामाजिक, धार्मिक और मांगलिक आयोजनों में हुड़दंग की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। इन घटनाओं से महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है और समाज में भय और असुरक्षा का वातावरण निर्मित हो गया है। समाज संगठनों ने अवैध शराब के निर्माण, भंडारण, परिवहन और विक्रय को जिले में फैलती गंभीर समस्या बताया है। उनका कहना है कि यह सामाजिक बुराई के साथ कानूनन दंडनीय अपराध है, जिस पर कठोर अंकुश लगाना आवश्यक है। ज्ञापन में भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। पदाधिकारियों ने प्रशासन से मांग की है कि आदतन शराबियों पर निवारक कार्रवाई की जाए, संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस गश्त बढ़ाई जाए और विवाह, धार्मिक तथा अन्य मांगलिक आयोजनों में शराब सेवन पर पूर्ण प्रतिबंध सुनिश्चित किया जाए। उनका कहना है कि यदि समय रहते प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो सामाजिक संतुलन और अधिक बिगड़ सकता है। समाज के प्रतिनिधियों ने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन ने शीघ्र और ठोस कार्रवाई नहीं की तो वे उच्च प्रशासनिक अधिकारियों एवं वैधानिक मंचों का सहारा लेने के लिए बाध्य होंगे। ज्ञापन सौंपने वालों में भूरा यादव, जिला अध्यक्ष संत सिंगाजी गवली समाज संगठन, मुन्ना मानकर जिला अध्यक्ष कुनबी समाज, संतुलाल सूर्यवंशी अध्यक्ष मेहरा समाज, संदीप धुर्वे जिला अध्यक्ष एवं जिला पंचायत सदस्य, चैतराम कासदे अध्यक्ष संघर्षशील कोरकू समाज संगठन जिला बैतूल, राकेश गंगारे, अध्यक्ष ढोलेवार सूर्यवंशी कुनबी समाज संगठन, शिव गंगारे संगठन सचिव बैतूल, गोपाल बिहारे जिला कोषाध्यक्ष मेहरा समाज संगठन तथा युवा प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष चंद्रभान बडौदे सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।

आदिवासी बहुल बीजादेही में 6.15 लाख की सीसी सड़क पर घमासान

फ्यूरी मशीन से निर्माण का आरोप, स्थानीय मजदूरों को नहीं मिला काम; ठेकेदारी और कमीशन की चर्चा के बीच ग्रामीणों ने मांगी उच्च स्तरीय जांच

शाहपुर । जनपद पंचायत शाहपुर अंतर्गत आदिवासी बहुल ग्राम बीजादेही में ब्रज के घर से बाजार चौक तक 200 मीटर लंबी सीसी सड़क का निर्माण कार्य गंभीर विवादों में घिर गया है। पांचवें राज्य वित्त आयोग की 6 लाख 15 हजार रुपये की राशि से स्वीकृत इस निर्माण को लेकर ग्रामीणों ने रोजगार से वंचित किए जाने, ठेकेदारी व्यवस्था और नियमों की अनदेखी के आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों के अनुसार निर्माण कार्य ठेकेदार के माध्यम से कराया जा रहा है और स्थल पर फ्यूरी मशीन का उपयोग किया जा रहा है। यह मशीन स्वयं गिट्टी, पानी और सीमेंट लेकर मिश्रण तैयार करती है, जिससे बड़ी संख्या में मजदूरों की आवश्यकता नहीं पड़ती।ग्रामीणों का कहना है कि जहां पहले ऐसे कार्यों में दर्जनों श्रमिकों को रोजगार मिलता था, वहीं अब एक मशीन ही कई मजदूरों का काम कर रही है।

ग्राम के कमलेश अखंडे, सुखराम काजले सहित अन्य ग्रामीणों ने बताया कि गांव के मजदूरों को काम पर नहीं लगाया जा रहा। उनका आरोप है कि जो कुछ श्रमिक कार्य स्थल पर दिख रहे हैं, वे भी ठेकेदार के ही लोग हैं। बुधवार को ग्राम की कई महिलाएं मजदूरी की मांग लेकर स्थल पर पहुंचीं, लेकिन उन्हें यह कहकर वापस भेज दिया गया कि यह काम ठेकेदार के लोग करेंगे। इस घटना के बाद महिलाओं में भी आक्रोश है। बीजादेही आदिवासी बहुल क्षेत्र है, जहां रोजगार के साधन अत्यंत सीमित हैं। बड़ी संख्या में ग्रामीण आजीविका के लिए अन्य शहरों की ओर पलायन करते हैं। ऐसे में पंचायत स्तर के निर्माण कार्य स्थानीय रोजगार का महत्वपूर्ण आधार माने जाते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यदि इन कार्यों में भी मशीनों और बाहरी श्रमिकों को प्राथमिकता दी जाएगी तो स्थानीय परिवारों के सामने रोजी-रोटी का संकट और गहराएगा। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के प्रावधानों के अनुसार ग्राम पंचायतों द्वारा कराए जाने वाले निर्माण कार्यों में पारदर्शिता, मस्टर रोल का विधिवत संधारण, श्रम व सामग्री मद का स्पष्ट पृथक्करण तथा स्थानीय श्रमिकों को प्राथमिकता अनिवार्य है। ऐसे में ग्रामीण सवाल उठा रहे हैं कि यदि निर्माण मुख्यतः मशीन के माध्यम से हो रहा है तो मजदूरी मद की राशि का लेखा-जोखा किस प्रकार दर्ज किया जा रहा है। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया है कि पंचायत स्तर पर कई बार कार्य ठेके या कथित कमीशन के आधार पर सौंपे जाते हैं और बाद में बिलों के माध्यम से राशि आहरित कर ली जाती है। हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ग्रामीणों ने पूरे मामले की तकनीकी एवं वित्तीय जांच की मांग की है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो वे उच्च अधिकारियों के समक्ष सामूहिक शिकायत दर्ज कराएंगे।

आग और जहरीली गैस से बचाव की सीख सतपुड़ा थर्मल प्लांट ने नगर पालिका कर्मियों को दिया फायर सेफ्टी प्रशिक्षण

सारनी। आकस्मिक आपदाओं से सुरक्षित रहने और आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुक्रवार को नगर पालिका कार्यालय सारनी में सतपुड़ा ताप विद्युत गृह द्वारा विशेष फायर सेफ्टी एवं डिजास्टर मैनेजमेंट प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में आग लगने की घटनाओं से बचाव के साथ-साथ खतरनाक रासायनिक गैस क्लोरिन से सुरक्षा के उपायों की विस्तृत जानकारी दी गई।सतपुड़ा ताप विद्युत गृह के डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत आयोजित इस प्रशिक्षण में अग्निशमन यंत्रों के प्राथमिक उपयोग का व्यावहारिक प्रदर्शन किया गया।विशेषज्ञों ने बताया कि आपदा के शुरुआती क्षणों में सही निर्णय और उपकरणों का सही उपयोग बड़े हादसों को टाल सकता है।कार्यक्रम सतपुड़ा प्लांट के मुख्य अभियंता (उत्पादन) के निर्देशानुसार अग्निशमन सेवा एवं संरक्षा विभाग द्वारा आयोजित किया गया।प्रशिक्षण के दौरान नगर पालिका क्षेत्र के कार्यालयीन कर्मचारियों एवं विद्यार्थियों के लिए चलाए जा रहे फायर सेफ्टी इंडक्शन अभियान की जानकारी भी साझा की गई। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष किशोर बरदे,वाहन शाखा प्रभारी के.के. भावसार,उपअग्निशमन अधिकारी हरिराम रघुवंशी, लीडिंग फायरमैन राहुल सालोडे,तकनीकी विशेषज्ञ (फायर) अजय डागी,महेंद्र, गोकुल तथा नगर पालिका की ओर से हरिओम कुशवाहा सहित अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे। सतपुड़ा प्लांट एवं नगर पालिका के फायर फाइटिंग विभागों द्वारा संयुक्त रूप से किए गए इस प्रदर्शन में कर्मचारियों को आग बुझाने के उपकरणों के सही उपयोग,आपातकालीन प्रतिक्रिया और क्लोरिन गैस रिसाव जैसी खतरनाक परिस्थितियों में सुरक्षित रहने के व्यावहारिक उपाय सिखाए गए।कार्यक्रम के अंत में अधिकारियों ने कहा कि जागरूकता और प्रशिक्षण ही किसी भी आपदा से बचाव का सबसे प्रभावी माध्यम है, जिससे जनहानि और संपत्ति के नुकसान को काफी हद तक रोका जा सकता है।

आजीविका मिशन अंतर्गत प्रशिक्षण के दौरान बिना अनुमति सामुहिक कार्यक्रम में शामिल हुई महिलाएं

जिम्मेदारों की लापरवाही आ रही सामने, अनहोनी हुई तो जिम्मेदार कौन

बैतूल राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत समुदायिक प्रशिक्षण केन्द्र भैसदेही में महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है, जहां महिलाओं के ठहरने और भोजन सहित व्यवस्थाएं रहती है। इस प्रशिक्षण केन्द्र में भैंसदेही के अलावा भीमपुर सहित अन्य ब्लाक की भी महिलाएं प्रशिक्षण हासिल करने पहुंचती है, किसी विशेष के फोन पर प्रशिक्षण उपरांत कुछ महिलाएं बिना अनुमति के सामुहिक कार्यक्रम में शामिल होने चली गई। जिसकी सोशल मिडिया मे फोटोस भी वाइरल हो रही है इससे जिम्मेदार अधिकारियों, प्रभारीयो की निगरानी और जिम्मेदारी पर सवाल खड़े हो रहे है। जानकारों का कहना है कि बिना अनुमति महिलाओं का प्रशिक्षण के दौरान सामुहिक कार्यक्रम में शामिल होना उचित नहीं है। जिम्मेदार अधिकारी को इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए, लेकिन अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे है। कार्यालय प्रभारी की कार्यशैली पर सवाल उठते है जिससे महिलाएं अपनी मनमर्जी से आना-जाना कर रही है। सूत्र बताते है कि प्रशिक्षण के दौरान अन्य विकासखंड से आई महिलाएं विगत कुछ दिनो सामुहिक कार्यक्रम जो कि रात्रि समय में था लेकिन बगैर किसी अनुमति के भी शामिल हुई। जिसकी जानकारी अधिकारियों तक को नहीं थी। ऐसे में महिलाओं के साथ कोई अनहोनी

घटना होती है तो उनका जिम्मेदार कौन होगा, यह बड़ा सवाल है। जानकारों का कहना है कि रात्रिकालीन समय में बिना अनुमति के महिलाओं का इस तरह सामुहिक कार्यक्रम में शामिल होना कहीं न कहीं जिम्मेदारों की लापरवाही पर भी प्रश्न उठाना है।

क्या कहते है जवाबदेह अधिकारी

प्रशिक्षण लेने के लिये जिले के कई ब्लाको से दीदीयो को प्रशिक्षण देने का कार्य किया जाता है इस दौरान दीदीयो के बिना अनुमति के बाहर जा रहे है तो कही ना कही प्रभारी की जिम्मेदारी होती है इसकी जांच करवाई जाएंगी ताकि कोई पुनरावृत्ति ना हो।

जुगल किशोर त्रिपाटी
सहायक ब्लाक समन्वयक
आजिविका मिशन भैसदेही

तोगाढाना आंगनवाड़ी केंद्र में सहायिका की नियुक्ति पर उठ रहे सवाल लगा फर्जी नियुक्ति का आरोप

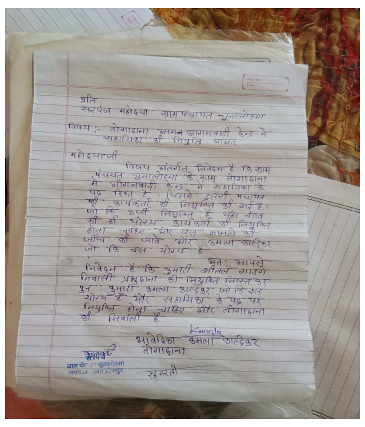

प्रति
सरपंज महोदया ग्राम पंचायत चुनालोहमा
विषय :- तोगाढाना आंगनवाड़ी केन्द्र में सहायिका की नियुक्ति बाबत
महोदयाजी
विषय अंतर्गत निवेदन है कि ग्राम पंचायत चुनालोहमा के ग्राम तोगाढाना में आंगनवाड़ी केन्द्र में सहायिका के पद रिक्त है, जिसमे इतरी पंचायत की कार्यकर्ता की नियुक्ति की गई है। जो कि फर्जी नियुक्ति है यहा गांव की ही योग्य कार्यकर्ता की नियुक्ति होना चाहिए और इस मामले की जांच की जावे और कमला धारिकर जो कि बस योग्य है
अतः आपसे निवेदन है कि कुमारी शीतल गाड्गे निवासी प्रभुढाना की नियुक्ति निरस्त कर पुनः कुमारी कमला धारिकर जो कि इस योग्य है और सहायिका के पद पर नियुक्ति होना चाहिए और तोगाढाना की निवासी है
आवेदिका कमला धारिकर
तोगाढाना
[illegible]
ग्राम पंचायत चूनालोहमा
जनपद पंचायत भीमपुर

संवाददाता

खेडिसावलीगढ़ विकासखंड भीमपुर की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत चुना लोहमा ग्रामपंचायत के अंतर्गत ग्राम तोगाढाना आंगनवाड़ी केंद्र में महिला बाल विकास के अधिकारियों पर गलत तरीके से सहायिका की नियुक्ति गुपचुप तरीकें से कर दी गई जब की ग्राम पंचायत क्षेत्र की ग्रेजूववेशन प्राप्त उम्मीदवारों को इसकी नियुक्ति के पूर्व सूचना दिए जाना था लेकिन जिनके जिम्मेदारी से यह नियुक्ति की गईहै वह गलत है यह आरोप ग्रामसरपंच एवम ग्रामीणों ने की हैग्रामीणों ने अपनी शिकायत में बतायाकी चुनालोहमा ग्राम पंचायत क्षेत्र केअभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जानीचाहिए लेकिन अधिकारी ने नियमऔर कायदों को ताक पर रखकर ग्राम पंचायत रातामाटी की रहनेवाली अभ्यर्थी को पद पर नियुक्तकर दिया जिससे ग्राम सरपंच सहित ग्रामीणों ने दावे आपत्तिभी दर्ज की लेकिन सवाल यहउठता है की ऐसा क्यों किया गया इस ग्राम पंचायत के लोगो कोखबर किए बिना आखिर कैसे होगई सहायिका की नियुक्ति इसकी संपूर्ण जांच की जानी चाहिएजिससे सच्चाई सामने आ जाए

उपनपा कार्यालय पाथाखेड़ा में हुआ संकल्प से समाधान अभियान का शिविर

सारनी।संकल्प से समाधान अभियान के तहत शुक्रवार को वार्ड 18 एवं 19 के लिए उप नगर पालिका कार्यालय पाथाखेडा में शिविर का आयोजन किया गया।मध्यप्रदेश शासन के निर्देशानुसार शासन की विभिन्न जन हितैषी योजनाओं का लाभ आम लोगों को देने के लिए 16 फरवरी से 15 मार्च तक संकल्प से समाधान अभियान के द्वितीय चरण का आयोजन किया जा रहा है।अभियान के तहत शुक्रवार को वार्ड 18 एवं 19 के लिए शिविर

का क्षेत्रीय उप नगर पालिका कार्यालय पाथाखेडा प्रांगण में आयोजन किया गया। इस दौरान लोगों को केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न जनहितैषी योजनाओं की जानकारी दी गई।शिविर में नगर पालिका अध्यक्ष किशोर बरदे,पार्षद मो. ताहिर अंसारी,जफर अंसारी, शिविर प्रभारी जीएस पांडे, आंगनबाडी कार्यकर्ता अन्य नागरिक उपस्थित थे। शिविर में विभिन्न योजनाओं के आवेदन आए। इनका समय सीमा में निराकरण किया जाएगा।

खाटूश्याम बाबा दरबार से निकली भव्य निशान यात्रा सैकड़ो श्रद्धालुओं ने किए दर्शन

संवाददाता

आमला। नगर के रेलवे पटरी स्थित खाटू श्याम बाबा मंदिर आमला से फाल्गुन माह के पावन अवसर पर श्रद्धा और भक्ति से ओत-प्रोत भव्य निशान यात्रा निकाली गई। यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए और जयकारों से पूरा नगर भक्तिमय हो उठा। निशान यात्रा मंदिर प्रांगण से प्रारंभ होकर हवाई पट्टी, टण्डन कैम्प, बोडखी सहित नगर के विभिन्न प्रमुख मार्गो से होते हुए शहर भ्रमण पर निकली। जगह-

जगह श्रद्धालुओं द्वारा पुष्पवर्षा कर यात्रा का स्वागत किया गया। महिलाओं, पुरुषों एवं युवाओं ने हाथों में निशान धारण कर भजन-कीर्तन के साथ बाबा श्याम के जयकारे लगाए। यात्रा के दौरान भक्ति संगीत और ढोल-ताशों की धुन पर श्रद्धालु झूमते नजर आए। मार्ग में सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद रहा। अंत में यात्रा पुनः खाटू श्याम मंदिर पहुंची, जहां विधिवत पूजा-अर्चना एवं आरती के साथ निशान यात्रा का समापन किया गया। पूरे आयोजन ने नगर के वातावरण को भक्तिमय बना दिया और श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह देखने को मिला

भीमपुर आंदोलन ने खोली व्यवस्था की परतें

नोडल मंत्रालय के मंत्री होने के बावजूद पट्टों के लिए तरस रहे बैतूल जिले के आदिवासी

जयस, समस्त आदिवासी संगठन और सर्व समाज संगठन के बैनर तले किसानों ने किया जोरदार आंदोलन

वनभूमि से विस्थापन का लगाया आरोप, नोडल मंत्रालय होते हुए भी वनाधिकार पट्टे अटके

बैतूल। जिस जिले का प्रतिनिधित्व केंद्रीय जनजाति कार्य राज्य मंत्री करते हैं, उसी जिले में आदिवासियों के वनाधिकार दावे लंबित पड़े हों तो सवाल उठना स्वाभाविक है। भीमपुर में जयस, समस्त आदिवासी संगठन और सर्व समाज संगठन के बैनर तले किसानों ने इसी मुद्दे पर जोरदार आंदोलन कर प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सीधा हमला बोला। वनाधिकार पट्टों से लेकर बिजली कटौती, ट्रांसफॉर्मर धोखाधड़ी, ताप्ती मेघा रिचार्ज, ढेंगना जलाशय परियोजना और अतिक्रमण तक, हर मुद्दे पर तत्काल कार्रवाई की मांग की गई। जयस प्रदेश संयोजक जामवन्त सिंह कुमरे ने कहा कि केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री दुर्गादास उईके का मंत्रालय व्यक्तिगत और सामुदायिक वनाधिकार दावों का नोडल मंत्रालय है, जो वनाधिकार अधिनियम के तहत कानून संबंधी मामलों की निगरानी करता है और मासिक प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा करता है। तारांकित प्रश्न 949 के जवाब में मंत्री ने 5 फरवरी 2026 को 44,33,940 व्यक्तिगत और सामुदायिक दावे की बात बताई है, जो किसी एक प्रदेश के अधिकारो के बराबर है, जो सरकार की नीयत में खोट को

दर्शाता है।

- हजारों सामुदायिक वनाधिकार पट्टे लंबित

वहीं बैतूल जिले में ग्राम पंचायत स्तर पर मुठवा देवस्थान, पेनकड़ा, खंडराई, श्मशान, गौठान और चरनोई भूमि के हजारों सामुदायिक वनाधिकार पट्टे लंबित हैं। उन्होंने कहा कि जब राज्य स्तरीय निगरानी समिति तिमाही बैठक कर सत्यापन और अंतरण की समीक्षा करती है, तब जिले में यह स्थिति प्रशासनिक उदासीनता को दर्शाती है। आंदोलन में वक्ताओं ने आरोप लगाया कि ताप्ती मेघा रिचार्ज, ताप्ती कंजरवेशन रिजर्व, फायरिंग रेंज, अभयारण्य और खनिज उत्खनन के नाम पर आदिवासी भूमि पर दबाव बनाया जा रहा है।

- लगातार बिजली कटौती से किसानों की फसलें प्रभावित

ढेंगना जलाशय परियोजना को लेकर भी विस्थापन की आशंका जताई गई। साथ ही भीमपुर क्षेत्र में लगातार बिजली कटौती से किसानों की फसलें प्रभावित होने और विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित होने की बात उठाई गई। ट्रांसफॉर्मर लगाने के नाम पर निजी ठेकेदारों द्वारा किसानों से अवैध वसूली और राशि लेकर फरार होने के आरोप लगाते हुए सख्त एफआईआर और कड़े कानून की मांग की गई। आंदोलनकारियों ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि वनाधिकार पट्टों और अन्य मांगों पर शीघ्र ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो भीमपुर से उठी यह आवाज बड़े आंदोलन में बदल सकती है।

सतलोक आश्रम में 268 यूनिट रक्तदान, 30 जोड़ो का दहेज मुक्त विवाह,1832 लोगों ने लिया देहदान का संकल्प

बैतूल। संत रामपाल महाराज के सानिध्य में सतलोक आश्रम उड़दन में महा विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। तीन दिनों तक चलने वाले इस महाविशाल समागम में लाखों की तादाद में भक्तगण आकर भंडारा प्रसादी ग्रहण कर रहे हैं। शुक्रवार को कार्यक्रम के दूसरे दिन संत गरीबदास महाराज के बोध दिवस के उपलक्ष्य में 26 से 28 फरवरी तक महा विशाल समागम मनाया जा रहा है, जिसमें 3 दिवसीय महा विशाल भंडारा व संत गरीबदास महाराज की अमृतमय वाणी का अखंड पाठ आयोजित किया गया है, साथ ही अन्य कार्यक्रम जैसे रक्त दान शिविर, देहदान शिविर, दहेज मुक्त विवाह का आयोजन किया गया। इस बार 30 जोड़ों का दहेज मुक्त विवाह संपन्न हुआ जो महज़ 17 मिनट में ही गुरुवाणी के माध्यम से संपन्न हुआ। रक्तदान-महादान में सैकड़ों अनुयायियों ने

भाग लिया और बैतूल जिला चिकित्सालय की टीम को 268 यूनिट रक्तदान किया गया। इस समागम में प्रेरणादाई प्रदर्शनी भी लगाई गई है। इस प्रदर्शनी के माध्यम से संत गरीबदास महाराज के जीवन के बारे में बताया। सतलोक आश्रम में लाखों की तादाद में श्रद्धालु भंडारा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। सतलोक आश्रम में कई राज्यों से संगत आ रही है भीड़ भाड़ में किसी को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो इसके लिए भी पूरी व्यवस्था की गई है। भंडारे में शुद्ध देशी घी से निर्मित मिष्ठान सब्जी,पुड़ी, दाल,चावल, सलाद चौबीसों घंटे लगातार वितरित किया जा रहा है। संत रामपाल महाराज जी द्वारा दिए गए तत्वज्ञान से प्रभावित होकर 3861 लोगो ने निःशुल्क नामदीक्षा ग्रहण की साथ ही संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाए जा रहे समाज सुधार के कार्यों में योगदान देते हुए 1832 अनुयायियों द्वारा देहदान के संकल्प फॉर्म भरें हैं। श्रद्धालु मुक्त कंठ से आयोजन कि प्रशंसा कर रहें हैं और भंडारे में लाखों की तादाद में लोग आ रहे हैं।

शिक्षा में न्यायपालिका : संवाद की जरूरत या विवाद की राजनीति?

ललित गर्ग

शिक्षा का उद्देश्य केवल तथ्य देना नहीं, दृष्टि देना है। यदि हम बच्चों को यह सिखाते हैं कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार है, तो साथ ही यह भी सिखाना होगा कि न्यायपालिका ने भ्रष्टाचार से लड़ने में कैसी भूमिका निभाई है, उसने प्रशासनिक दुरुपयोग पर कैसे अंकुश लगाया है, नागरिक अधिकारों की रक्षा में कैसे ऐतिहासिक निर्णय दिए हैं। एक बार फिर शिक्षा से जुड़ा एक प्रश्न राष्ट्रीय विमर्श के केंद्र में है। शिक्षा मंत्रालय और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) द्वारा प्रकाशित आठवीं कक्षा की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक में हमारे समाज में न्यायपालिका की भूमिका शीर्षक अध्याय में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार और लंबित मुकदमों का उल्लेख किए जाने पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय ने नाराजगी प्रकट की। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की यह टिप्पणी कि किसी को भी न्यायपालिका को बदनाम करने नहीं दिया जाएगा केवल एक भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि संस्थागत गरिमा की रक्षा का संकेत है। इसके बाद संबंधित अध्याय को हटाने और बाजार में उपलब्ध पुस्तकों को वापस लेने का निर्णय लिया गया। प्रश्न यह है कि क्या यह केवल एक संपादकीय चूक थी या हमारे शैक्षिक ढांचे में कहीं गहरी संरचनात्मक कमी है? प्रश्न है कि स्कूली बच्चों को 'न्यायपालिका में भ्रष्टाचार' के बारे में जानकारी देने से किस हित की पूर्ति होने वाली है? लेकिन इसमें दो मत नहीं है कि न्यायिक तंत्र के साथ हर क्षेत्र में फैली भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के ठोस उपाय होने ही चाहिए। सबसे पहले यह भी स्वीकार करना होगा कि न्यायपालिका में लंबित मामलों और भ्रष्टाचार जैसे प्रश्न पूरी तरह काल्पनिक नहीं हैं। न्यायालयों में लंबित मुकदमों की संख्या करोड़ों में है, यह एक सार्वजनिक तथ्य है। कुछ मामलों में न्यायिक आचरण पर भी प्रश्न उठे हैं। परंतु उतना ही सत्य यह भी है कि भारतीय न्यायपालिका ने समय-समय पर अपनी स्वतंत्रता, पारदर्शिता और सक्रियता से लोकतंत्र की रक्षा की है। पिछले वर्षों में शीर्ष न्यायाधीशों द्वारा अपनी संपत्तियों का सार्वजनिक विवरण देने की सहमति जैसे कदमों ने संस्थागत पारदर्शिता को सुदृढ़ किया है। ऐसे में प्रश्न यह नहीं है कि समस्या है या नहीं, प्रश्न यह है कि उसे किस भाषा, किस संतुलन और किस शैक्षिक दृष्टि से प्रस्तुत किया जाए।

शिक्षा का उद्देश्य केवल तथ्य देना नहीं, दृष्टि देना है। यदि हम बच्चों को यह सिखाते हैं कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार है, तो साथ ही यह भी सिखाना होगा कि न्यायपालिका ने भ्रष्टाचार से लड़ने में कैसी भूमिका निभाई है, उसने प्रशासनिक दुरुपयोग पर कैसे अंकुश लगाया है, नागरिक अधिकारों की रक्षा में कैसे ऐतिहासिक निर्णय दिए हैं। शिक्षा में आलोचना हो, पर निराशा नहीं, तथ्य हों, पर संतुलन भी हो। यदि किसी अध्याय में केवल संस्थागत विकृतियों का उल्लेख हो और सुधारात्मक प्रयासों, आदर्श उदाहरणों और संवैधानिक मूल्यों का समुचित विवेचन न हो, तो वह शिक्षा में मूल्यों एवं आदर्शों के बजाय अविश्वास का बीजारोपण बन सकता है। यह विवाद एक बड़े प्रश्न को भी जन्म देता है-पाठ्य पुस्तकों की निर्माण प्रक्रिया में बहुस्तरीय समीक्षा के बावजूद ऐसी सामग्री कैसे प्रकाशित हो जाती है? क्या संपादकीय बोर्ड में विविध दृष्टिकोणों का अभाव है? क्या विधि विशेषज्ञों, शिक्षाशास्त्रियों और मनोवैज्ञानिकों के बीच समन्वय पर्याप्त नहीं है? एक लोकतांत्रिक समाज में संस्थाओं की आलोचना वर्जित नहीं हो सकती, पर आलोचना और अवमूल्यन के बीच महीन रेखा होती है। शिक्षा मंत्रालय और एनसीईआरटी जैसी संस्थाओं का दायित्व है कि वे इस रेखा को पहचानें।

यह भी स्मरणीय है कि भ्रष्टाचार केवल न्यायपालिका तक सीमित समस्या नहीं है। हाल ही में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की इसी महीने जारी रिपोर्ट के मुताबिक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में 182 देशों के बीच भारत की रैंक 91 है। पिछले साल के मुकाबले भारत ने 5 स्थान का सुधार किया है, यह स्थिति सुधार के बावजूद मध्य स्तर पर बनी हुई बताई गई है। इसका अर्थ है कि भ्रष्टाचार एक संरचनात्मक, सामाजिक और प्रशासनिक चुनौती है। यदि हम बच्चों को इसके बारे में पढ़ाते हैं तो उसे एक समग्र सामाजिक संदर्भ में पढ़ाया जाना चाहिए कि यह समस्या क्यों उत्पन्न होती है, इसे रोकने के लिए क्या संवैधानिक तंत्र हैं, नागरिकों की क्या भूमिका है और सुधार की संभावनाएं क्या हैं। केवल किसी एक संस्था को केंद्र में रखकर समस्या का चित्रण करना न तो शैक्षिक रूप से न्यायोचित है और न ही संवैधानिक संतुलन के अनुरूप। न्यायपालिका की गरिमा का प्रश्न भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र तीन स्तंभों-विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका पर आधारित है। यदि किसी एक स्तंभ के प्रति बच्चों के मन में अविश्वास की भावना बिना सम्यक् विश्लेषण के उत्पन्न हो जाए, तो यह दीर्घकाल में लोकतांत्रिक संस्कृति के लिए हानिकारक हो सकता है। परंतु गरिमा की रक्षा का अर्थ यह भी नहीं कि समस्याओं पर मौन साध लिया जाए। गरिमा और पारदर्शिता परस्पर विरोधी नहीं, बल्कि पूरक हैं। न्यायपालिका की वास्तविक प्रतिष्ठा उसकी आलोचना सहने की क्षमता, आत्मसुधार की तत्परता और नैतिक दृढ़ता से बढ़ती है। इस संदर्भ में एक नई शैक्षिक संरचना की आवश्यकता अनुभव होती है। पाठ्य पुस्तकों में संस्थागत अध्ययन का प्रारूप इस प्रकार विकसित किया जा सकता है जिसमें तीन आयाम हों-संविधान द्वारा प्रदत्त भूमिका, वास्तविक चुनौतियां और सुधार की पहल। उदाहरण के लिए, न्यायपालिका पर अध्याय में उसके ऐतिहासिक निर्णय, जनहित याचिका की परंपरा, मौलिक अधिकारों की रक्षा, साथ ही लंबित मामलों की समस्या और न्यायिक सुधार आयोगों की सिफारिशों का संतुलित उल्लेख किया जाए। इससे छात्र न तो अंधभक्त बनेंगे और न ही निंदक, वे सजग नागरिक बनेंगे। शिक्षा मंत्रालय को भी इस अवसर को आत्ममंथन के रूप में लेना चाहिए। विवाद के बाद अध्याय हटाना तात्कालिक समाधान हो सकता है, पर स्थायी समाधान नहीं। आवश्यकता है एक स्वतंत्र, बहुविषयी समीक्षा तंत्र की, जिसमें विधि विशेषज्ञ, पूर्व न्यायाधीश, शिक्षाशास्त्री, समाजशास्त्री और बाल मनोविज्ञान के जानकार शामिल हों। साथ ही, सार्वजनिक परामर्श की परंपरा विकसित की जा सकती है ताकि पाठ्य पुस्तकें केवल सरकारी दस्तावेज न रहकर सामाजिक सहमति का दस्तावेज बनें।

भारत इजराइल के बीच हुए 16 समझौते

25 फरवरी को इजराइल के दो दिन के दौरे पर पीएम मोदी गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इजराइल दौरा मुकम्मल हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजराइल के दौरे को आप भारत और इजराइलके रिश्तों का स्पेशल 27 भी कह सकते हैं क्योंकि करीब-करीब 27 घंटे का प्रधानमंत्री मोदी का ये इजराइल का दौरा था। 16 समझौते हुए हैं। 11 बड़े ऐलान हुए हैं। कुल 27 बाईलेटरल आउटकम्स। रिश्ते को नया नाम मिला है। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को अब स्पेशल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कहा जाएगा। लेकिन इन सब भारीभरकम शब्दों का मतलब क्या है? इस दौरे की पूरी बैलेंस शीट क्या कहती है? भारत और इस्राइल मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) को जल्द अंतिम रूप देंगे। रक्षा क्षेत्र में साझा डिवेलपमेंट, प्रॉडक्शन और टेक्नॉलजी ट्रांसफर पर काम करेंगे। संबंधों को विशेष रणनीतिक साझेदारी का दर्जा देंगे। भारत का PI पेमेंट सिस्टम इस्राइल में भी चलेगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच बैठक में रक्षा, सुरक्षा, व्यापार, AI, तकनीक और कृषि जैसे क्षेत्रों में ऐसे 16 समझौतों और सहमति पत्रों पर मुहर लगी। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी ने कहा कि पश्चिम एशिया क्षेत्र में शांति और स्थिरता से भारत के हित जुड़े हैं। हम कंधे से कंधा मिलाकर आतंकवाद और इसके समर्थकों का विरोध करते रहे है और आगे भी करते रहेंगे। भारत मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे और I22 (भारत-इस्राइल यूएई-अमेरिका समूह) के तहत सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। मोदी ने कहा कि भारत और इस्राइल ने क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नॉलजी पर साझेदारी क्वांटम और क्रिटिकल मिनरल्स जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नई गति मिलेगी। सिविल न्यूक्लियर एनर्जी और स्पेस में भी सहयोग बढ़ाएंगे।

दोनों देशों की बातचीत में तकनीक फोकस में रही, इसमें साइबर सेक्योरिटी, इनोवेशन और एआई, रिसर्च और स्टार्ट अप शामिल है। विज्ञान और तकनीक पर मौजूद जॉइंट कमिशन को मंत्रीस्तरीय दर्जे तक ले जाने का फैसला लिया गया। इससे इस क्षेत्र में समन्वय में मदद मिलेगी।भारत में इस्राइल की मदद से चल रहे 43 सेंटर ऑफ एक्सीलेस को विस्तार देकर 100 करने पर फैसला। भारत में भारत में एग्रीकल्चर इनोवेशन सेंटर फॉर एग्रीकल्चर की स्थापना होगी।दोनों प्रधानमंत्रियों ने ईरान और अमेरिका के मौजूदा तनाव को लेकर बातचीत की। शांति से बातचीत पर जोर दिया। कहा, गाजा के पुनर्निमाण में भी भूमिका देख रहे है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इस दौरान इस्त्राइल के राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग से मुलाकात की और दोनों नेताओं ने शिक्षा, स्टार्टअप, नवाचार, प्रौद्योगिकी और कनेक्टिविटी के क्षेत्र में सहयोग को और बढ़ाने पर विचार-विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत-इस्त्राइल विशेष साझेदारी को मजबूत करने में राष्ट्रपति हर्जोग के अटूट समर्थन के लिए उनका धन्यवाद किया। उन्होंने इस्त्राइल के राष्ट्रपति को भारत आने का न्योता भी दिया।भारत और इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर दूसरे दौर की बातचीत मई में करेंगे। यह वार्ता इस्त्राइल में होगी। राष्ट्रीय राजधानी में रविवार से शुरू हुआ वार्ता का पहला दौर गुरुवार को पूरा हुआ।

मोदी की इजरायल यात्रा संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम

कमलेश पांडे

देखा जाए तो यह 2017 के बाद पीएम मोदी की दूसरी इजरायल यात्रा 2026 में हुई, जो द्विपक्षीय व्यापार को कई अरब डॉलर तक ले जाने में सहायक सिद्ध हुई। जहां तक इस यात्रा के रणनीतिक महत्व की बात है तो यह यात्रा बढ़ते ईरान-अमेरिका तनाव और अमेरिकी नौसेना की तैनाती के बीच हुई, जो इजरायल को मजबूती प्रदान करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया इजरायल यात्रा भारत-इजरायल संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो वैश्विक भू-राजनीति में बदलते समीकरणों को दर्शाती है। यह यात्रा पश्चिम एशिया की अस्थिरता के बीच रणनीतिक साझेदारी को नई दिशा देती है। इस बार मोदी ने इजरायल संसद केनेसेट को संबोधित किया, जहां उन्होंने 7 अक्टूबर 2023 हमले के बाद भारत के इजरायल समर्थन की पुष्टि की और ईरान द्वारा शह प्राप्त हमास की मानवता द्रोही कार्रवाई की भर्त्सना की। इसके अलावा, नेतन्याहू के साथ द्विपक्षीय वार्ता में रक्षा, व्यापार और आतंकवाद विरोधी सहयोग पर जोर दिया।

देखा जाए तो यह 2017 के बाद पीएम मोदी की दूसरी इजरायल यात्रा 2026 में हुई, जो द्विपक्षीय व्यापार को कई अरब डॉलर तक ले जाने में सहायक सिद्ध हुई। जहां तक इस यात्रा के रणनीतिक महत्व की बात है तो यह यात्रा बढ़ते ईरान-अमेरिका तनाव और अमेरिकी नौसेना की तैनाती के बीच हुई, जो इजरायल को मजबूती प्रदान करती है। वहीं नेतन्याहू का प्रस्तावित हेक्सागन गठबंधन (भारत, इजरायल, ग्रीस, साइप्रस आदि) चीन-पाकिस्तान-तुर्की धुरी के विरुद्ध एक रणनीतिक संतुलन भी बनाता है। यह वैश्विक कूटनीति में नहले पर दहले की तरह समझा जा रहा है। जिस तरह से भारत, इजरायल का सबसे बड़ा हथियार खरीदार बन चुका है, उससे दक्षिण एशिया और मध्य पूर्व की सुरक्षा का समीकरण प्रभावित होना स्वाभाविक है। इससे अमेरिका, चीन, रूस और यूरोपीय देशों को भी भारत की कूटनीतिक स्वायत्तता का एहसास हुआ है, जो भारत को एशिया की दूसरी और दुनिया की तीसरी-चौथी महत्वपूर्ण शक्ति बनाने की दिशा में सक्रिय है। जहां तक इस यात्रा के आर्थिक आयामों की बात है तो दोनों देशों के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (स्न्नञ्ज) पर सकारात्मक चर्चा हुई, जो दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं के लिए गेम-चेंजर साबित हो सकता है। खासकर ढ्ढरूश्वष्ट कॉरिडोर (भारत-मध्य पूर्व-यूरोप) पर ...श्व के साथ त्रिपक्षीय सहयोग से वैश्विक व्यापार को एक नया आकार मिलने की संभावना है। वहीं कृषि, जल प्रबंधन और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों में इजरायली विशेषज्ञता भारत के विकास को काफी बढ़ावा देगी।

शायद यही वजह है कि अरब जगत में खलबली मची है और इस्लामिक कट्टरता को हवा देने वाले पश्चिमी और पूर्वी देशों में बेचैनी भी। इस प्रकार की वैश्विक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। जहां मोदी की इजरायल यात्रा से इस्लामी देशों की मीडिया में खलबली मची, क्योंकि यह इस्लामी उग्रवाद विरोधी एक्सिस का संकेत माना गया। वहीं फिलिस्तीन समर्थन बनाए रखते हुए अमेरिका को सिग्नल देते हुए भारत ने ग्लोबल साउथ में संतुलित भूमिका निभाई।

वहीं इस यात्रा ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की वैश्विक छवि को मजबूत किया, जो गाजा संकट के बीच चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं कि आए दिन बढ़ते वैश्विक इस्लामिक कट्टरता परस्त आतंकवाद, भीड़ हिंसा और लक्षित हमलों से भारत और इजरायल दोनों को खतरा है, इसलिए उनकी पारस्परिक और लाभप्रद एकजुटता भारत-इजरायल विरोधी देशों को चुभती रहती है।

चूंकि भारत और इजरायल के बीच पूर्ण राजनयिक संबंध 1992 में स्थापित हुए, जबकि भारत ने 1950 में ही इजरायल को मान्यता दी थी। खासकर मोदी सरकार के नेतृत्व में 2014 से द्विपक्षीय संबंध तेजी से मजबूत हुए, जिसमें उच्च स्तरीय यात्राएं और रक्षा-सहयोग प्रमुख रहे। इससे द्विपक्षीय लाभ में वर्ष दर वर्ष बढ़ोतरी दृष्टिगोचर हुई। रक्षा और सुरक्षा सहयोग के मद्देनजर इजरायल भारत का प्रमुख रक्षा आपूर्तिकर्ता है, जो ड्रोन, मिसाइल और खुफिया प्रणालियां प्रदान करता है। दोनों देश आतंकवाद विरोधी प्रयासों में एकजुट हैं, जो सीमा-पार खतरों से निपटने में सहायक सिद्ध होता है। जहां तक आर्थिक और तकनीकी साझेदारी की बात है तो व्यापार में भारत इजरायल का एशिया में दूसरा सबसे बड़ा साझेदार है, जिसमें कृषि, जल प्रबंधन, एआई और क्वांटम कंप्यूटिंग शामिल हैं। I22 (भारत, इजरायल, यूएई, अमेरिका) और IMEC जैसे मंच आर्थिक गलियारों को बढ़ावा देते हैं।

भारत-इजरायल की दोस्ती से भू-राजनीतिक प्रभाव भी बढ़ा है। यह दोस्ती जहां चीन की मध्य पूर्व और दक्षिण एशिया में बढ़ती प्रभाव को संतुलित करने में मदद करती है। वहीं ईरान-प्रभावित क्षेत्रों में वैकल्पिक ध्रुव बनाकर स्थिरता सुनिश्चित होती है, जबकि भारत फिलिस्तीन समर्थन बनाए रखता है। इससे वैश्विक मंचों पर भी सामंजस्य बढ़ा है। खासकर संयुक्त राष्ट्र जैसे मंचों पर दोनों आतंकवाद-विरोध और सुधारों पर सहमत हैं। 2026 में संयुक्त कार्ययोजना से कूटनीति, साइबर और संस्कृति में सहयोग बढ़ेगा। यह भारत की रणनीतिक स्वायत्तता को मजबूत करता है। भारत-इजरायल संबंधों को I22 गठबंधन ने नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। यह समूह (भारत, इजरायल, यूएई, अमेरिका) दोनों देशों के बीच सहयोग को बहुपक्षीय रूप प्रदान करता है। I22 ने जल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा जैसे छह क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा दिया है। भारत और इजरायल के बीच तकनीकी साझेदारी, जैसे सौर ऊर्जा परियोजनाएं और खाद्य पार्क, इसी से मजबूत हुई। जहां तक अब्राहम समझौते के लाभ की बात है तो अब्राहम समझौते के बाद यूएई-इजरायल संबंध सामान्य होने से भारत बिना फिलिस्तीन संबंधों को नुकसान पहुंचाए इजरायल से गहरा जुड़ाव बना पाया। इससे भारत की पश्चिम एशिया नीति में संतुलन आया। भू-राजनीतिक मजबूती मिली। यह गठबंधन चीन के मध्य पूर्व प्रभाव को काउंटर करता है, जबकि भारत-इजरायल रक्षा और साइबर सहयोग बढ़ा। I22 ने IMEC जैसे कॉरिडोर को सपोर्ट किया, जो भारत की कनेक्टिविटी रणनीति को मजबूत करता है। अतीत की बात करें तो मोदी की 2017 इजरायल यात्रा ने भारत-इजरायल संबंधों को ऐतिहासिक मोड़ दिया। यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी, जिसने द्विपक्षीय सहयोग को रणनीतिक साझेदारी का दर्जा प्रदान किया। इससे रक्षा सहयोग में उछाल आया। यात्रा के दौरान रक्षा समझौतों पर जोर दिया गया, जिसमें मिसाइल प्रणाली और ड्रोन तकनीक शामिल थी। नेतन्याहू के साथ मोदी की साझा सड़क यात्रा ने आतंकवाद-विरोधी एकजुटता को मजबूत किया।

वहीं कृषि और जल प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस परियोजनाओं का विस्तार हुआ, जो भारत के किसानों को ड्रिप इरिगेशन जैसी तकनीक प्रदान करती हैं। इनसे द्विपक्षीय व्यापार 5 बिलियन से अधिक पहुंचा। वहीं नवाचार और स्टार्टअप सेतु इनोवेशन ब्रिज पहल ने स्टार्टअप्स और साइबर सुरक्षा में सहयोग बढ़ाया। यात्रा ने I22 जैसे बहुपक्षीय मंचों की नींव रखी, जो अब्राहम समझौते से जुड़े। यह भारत की पश्चिम एशिया नीति को संतुलित बनाती है। खासकर मोदी की पिछली इजरायल यात्रा के दौरान सात प्रमुख समझौते हस्ताक्षरित हुए, जिन्होंने द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत आधार प्रदान किया। ये समझौते मुख्यत: कृषि, जल प्रबंधन, अंतरिक्ष और अनुसंधान पर केंद्रित थे। जल और कृषि क्षेत्र में गंगा सफाई, जल संरक्षण तथा स्वच्छता कार्यक्रमों के लिए यूपी जल निगम और इजरायल ऊर्जा-जल विभाग के बीच करार हुआ। कृषि विकास कार्यक्रम तथा ड्रिप इरिगेशन जैसी तकनीकों पर तीन वर्षीय कार्ययोजना बनी।

वहीं, अंतरिक्ष एवं नवाचार सहयोग से छोटे सैटेलाइट्स, परमाणु घड़ी निर्माण तथा जियो-लियो ऑप्टिकल लिंक पर तीन समझौते हुए। अनुसंधान एवं नवोन्मेष के लिए 260 करोड़ रुपये का साझा फंड स्थापित किया गया।

मिलन युद्धाभ्यास: भारत की नौसैना शक्ति का प्रदर्शन

अरुणेंद्र नाथ वर्मा

मध्य युग से आज तक सैन्य और आर्थिक रूप से शक्तिशाली देश अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए समुद्र की लहरों पर एकाधिपत्य जमाने का प्रयत्न करते आये हैं. हालांकि, साम्राज्यवाद का अब अंत हो चुका है, पर आज भी वैश्विक अर्थव्यवस्था सुदूर देशों के बीच फैले महासागरों में निरापद वाणिज्य पर टिकी हुई है. सुदूर दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला से भारत में खनिज, तेल का आयात या वियतनाम से अमेरिकी नागरिकों के लिए वस्त्र-परिधान का निर्यात, आज की अर्थव्यवस्था के ये दो छोटे-से नमूने सिद्ध करते हैं कि विश्व के सागर-महासागर दुनिया के समस्त देशों के साझा संसाधन और साझा पूंजी के रूप में देखे जाने चाहिए. भारत मानता है कि इक्कीसवीं सदी की चुनौतियों का समाधान एकाकी नहीं, सामूहिक प्रयासों में निहित है. सुरक्षित, मुक्त और संतुलित समुद्री क्षेत्र को वैश्विक शांति और समृद्धि की कुंजी मानकर भारत विभिन्न देशों के साथ समय-समय पर सैन्य अभ्यास आयोजित करता आया है और ऐसे आयोजनों में भाग लेता आया है.

हाल के वर्षों में मित्र देशों के साथ किये गये उल्लेखनीय युद्धाभ्यासों में प्रमुख था, मालाबार नौसैनिक युद्धाभ्यास. वर्ष 1992 में अमेरिका और भारत के संयुक्त प्रयास से आरंभ होने वाले इस अभ्यास में जापान और ऑस्ट्रेलिया भी जुड़कर अब क्वाड नाम से जाने जाते हैं. इसके अतिरिक्त, वरुण और गरुड़-25 (भारत-फ्रांस की नौसेनाओं का), इंद्र (रूस-भारत की तीनों सेनाओं का) और समुद्र शक्ति (भारत-इंडोनेशिया का) कुछ अन्य उदाहरण हैं. ऐसे युद्धाभ्यासों की शृंखला म जुड़न वाला अब तक का सबस बड़ा अभ्यास ह 15 फरवरी से 25 फरवरी तक विशाखापट्टनम में आयोजित बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास 'मिलन.' इस विशाल अभ्यास में शामिल 74 देशों की नौसेनाओं के 84 युद्धपोतों में भारतीय विमानवाहक पोत विक्रांत और पनडुब्बियों को मिलाकर 19 भारतीय नौसेनिक पोत थे. इन पोतों के कार्यकलाप में कठिन समुद्री युद्धाभ्यास, पनडुब्बी रोधी और हवाई रोधी अभ्यास शामिल हैं. 'मिलन' अभ्यास केवल भारत की नौसैन्य क्षमता और शक्ति का प्रदर्शन नहीं, बल्कि इस सम्मिलित युद्धाभ्यास का उद्देश्य भाग लेने वाली नौसेनाओं के बीच आपसी विश्वास, सहयोग और समन्वय बढ़ाना है. एक तरफ इसका तत्काल प्रभाव उन्नत युद्ध कौशल और बेहतर सामरिक क्षमता के रूप में दिखेगा, तो दूसरी तरफ इसका दीर्घकालीन उद्देश्य सामूहिक सुरक्षा, नियम आधारित व्यवस्था और परस्पर विश्वास बढ़ाना है.

भारत आज अमेरिका, चीन और रूस के बाद विश्व की चौथी बड़ी सैन्य शक्ति के रूप में जाना जाता है. उसके साथ अमेरिका, रूस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और ईरान जैसे देशों की नौसेनाओं का यह संयुक्त अभ्यास हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के क्षेत्र ही नहीं, पूरे विश्व के समुद्री व्यापार और ऊर्जा आपूर्ति की जीवनरेखा बनकर उभरेगा. समुद्री मार्गों की सुरक्षा, सभी देशों की साझा चिंता है. इसी पृष्ठभूमि में यह अभ्यास स्पष्ट करता है कि समुद्री डकैती, तस्करी, आतंकवाद और आपदाओं जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए बहुपक्षीय सहयोग अनिवार्य है. वर्ष 2024 में सोमालिया के जिन समुद्री लुटेरों ने ईरानी वाणिज्य पोतों पर कब्जा कर 19 पाकिस्तानी क्रू को बंदी बना लिया था, उन्हें भारतीय नौसेना पोत 'सुमित्रा' ने समर्पण करने के लिए मजबूर किया था।

लुटियंस दिल्ली में एक स्मारक अनाम मजदूरों का हो

विवेक शुक्ला

राष्ट्रपति भवन में ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लुटियंस की मूर्ति हटाकर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी की मूर्ति लगायी गयी है. यह कदम औपनिवेशिक सोच से बाहर निकलकर भारतीय विरासत को सम्मान देने की दिशा में एक संकेत माना जा रहा है. पर केवल प्रतीक बदल देने से बात पूरी नहीं हो जाती. हमें उन लोगों को भी याद करना चाहिए, जिन्होंने इन ऐतिहासिक भवनों को अपने हाथों से बनाया. नयी दिल्ली का निर्माण 1911 से 1931 के बीच हुआ, जब अंग्रेजों ने राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली लाने का निर्णय किया. उस समय लुटियंस मुख्य वास्तुकार थे और उनके साथ हर्बर्ट बेकर भी काम कर रहे थे. पर इन भव्य इमारतों को खड़ा करने का असली काम तो हजारों भारतीय मजदूरों ने किया था. निर्माण के दौरान करीब 30,000 श्रमिक दिन-रात मेहनत कर रहे थे, जिनमें सैकड़ों कुशल संगतराश भी शामिल थे.

ये मजदूर ज्यादातर राजस्थान के जयपुर, जोधपुर और भीलवाड़ा जैसे क्षेत्रों से आये थे. वे अपने परिवारों के साथ गांव छोड़कर दिल्ली पहुंचे और वहां अस्थायी बस्तियों में रहने लगे. उनकी मजदूरी बहुत कम थी- पुरुषों को एक रुपया रोज और महिलाओं को आधा रुपया, यानी अठन्नी. कम मेहनताना होने के

बावजूद उन्होंने पूरी लगन से काम किया और भव्य इमारतों को आकार दिया. पत्थरों पर बारीक नक्काशी करने वाले कई संगतराश आगरा, मिर्जापुर और भरतपुर से आये थे. उनके पूर्वज ताजमहल, लाल किला और जामा मस्जिद जैसे ऐतिहासिक स्मारकों के निर्माण में योगदान दे चुके थे. नयी दिल्ली की शान केवल मानचित्रों से नहीं, बल्कि इन मेहनतकश हाथों की मेहनत से बनी है. कम मजदूरी के बावजूद इन सीधे-सादे लोगों ने दिन-रात अथक मेहनत की. यहां काम कर रहे संगतराश पत्थरों पर नक्काशी, जालियां और बारीक काम में निपुण थे. राष्ट्रपति भवन के भव्य स्तंभ, संसद भवन की गोलाकार संरचना, नॉर्थ-साउथ ब्लॉक की शानदार नक्काशी- सबमें इन कारीगरों की कला और कौशल साफ दिखाई देता है. इन कारीगरों ने लाखों ईंटों और बड़ी मात्रा में पत्थरों से शानदार इमारतें खड़ी की थीं. इन भवनों के निर्माण में भारतीय ठेकेदारों की भूमिका भी कम महत्वपूर्ण नहीं थी. संसद भवन (तब काउंसिल हाउस या लेजिस्लेटिव चैंबर्स) के मुख्य ठेकेदार लक्ष्मण दास सिंध के थे. खुशवंत सिंह ने उन्हें 'सच्चाई और नेकनीयती की मिसाल' बताया है. लक्ष्मण दास ने कभी घटिया सामग्री इस्तेमाल नहीं की, मजदूरों को समय पर वेतन दिया और टैक्स में कभी कोई चोरी नहीं की. खुशवंत सिंह ने जितनी प्रशंसा लक्ष्मण दास की की है, उतनी प्रशंसा अपने पिता सर शोभा सिंह या अन्य ठेकेदारों की नहीं की, जबकि शोभा सिंह ने भी नयी दिल्ली की कई इमारतों का निर्माण किया था. लक्ष्मण दास मजदूरों के साथ घुल-मिलकर रहते थे, उनकी परेशानियां समझते थे. संसद भवन के उद्घाटन के समय लक्ष्मण दास मौजूद थे. उनका मिशन पूरा हो चुका था, इसका उन्हें संतोष था. पर उन्होंने नयी दिल्ली में कोई नया प्रोजेक्ट नहीं लिया. वह सिंध भी नहीं लौटे, हरिद्वार जाकर साधु बन गये, वहीं उनका निधन हुआ. यह उनकी सादगी, मानवीयता और निस्वार्थ सेवा का जीता-जागता प्रमाण है. समय बदल गया है. आज राजस्थान से दिल्ली में मजदूर कम आते हैं. जो तब आये थे, वे दिल्ली का अभिन्न अंग बन गये. उनके वंशज अब विभिन्न क्षेत्रों में सफल हैं- कई सामाजिक-आर्थिक रूप से मजबूत हैं, यहां तक कि मंत्री पद तक पहुंचे. जैसे, मदन लाल खुराना सरकार में सुरेंद्र रातावाल मंत्री थे, जिनके दादा और रिश्तेदारों ने संसद भवन बनाया था. रातावाल को इस विरासत पर गर्व है. आने वाली पीढ़ियां भी नयी ऊंचाइयां छू रही हैं और छुएंगी. राजधानी में आजकल सेंट्रल विस्टा और अन्य परियोजनाओं को पूरा करने के लिए हजारों मजदूर आये हुए हैं. ये एक प्रोजेक्ट के खत्म होने के बाद अगले प्रोजेक्ट से जुड़ जाते हैं. ये ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़ से हैं. दिल्ली के पुराने लोगों को याद होगा कि यहां पर 1982 के एशियाई खेलों के समय बहुत बड़ी तादाद में मजदूर आये थे. तब बिहार से काफी तादाद में मजदूर आये थे. अब बिहार से आने वाले मजदूरों की संख्या निश्चित रूप से बहुत कम हुई है. अब आते हैं मूल प्रश्न पर. क्या हम उन अज्ञात मजदूरों, संगतराशों और ठेकेदारों, जैसे लक्ष्मण दास, की याद में एक स्मारक नहीं बना सकते? राष्ट्रपति भवन या संसद भवन के आसपास, या किसी सार्वजनिक स्थान पर, जो इन लाखों हाथों को समर्पित हो. यह सिर्फ पत्थर नहीं होगा, बल्कि उन मेहनतकशों का प्रतीक होगा जिन्होंने नयी दिल्ली को खड़ा किया. लुटियंस की मूर्ति हटाना औपनिवेशिक प्रतीकों से मुक्ति है, पर असली मुक्ति तब होगी जब हम उन भारतीयों को याद करेंगे।

पीएचई विभाग की लापरवाही से दूषित पानी पीने को मजबूर हिवरखेड के ग्रामीण

जिला पंचायत सदस्य उर्मिला गव्हाड़े ने कलेक्टर से की शिकायत

बैतूल। प्रभात पट्टन ब्लाक के ग्राम हिवरखेड में हालात ऐसे बन गए हैं कि ग्रामीणों को मजबूरी में दूषित पानी पीना पड़ रहा है। पीएचई विभाग द्वारा ठेकेदार के माध्यम से चल रही नल-जल योजना अब सवालों के घेरे में है। गांव की मुख्य गलियों में वाल लगाने के लिए गहरे और लंबे गड्ढे खोदकर छोड़ दिए गए हैं, जिनमें नालियों का गंदा पानी जमा हो रहा है। आरोप है कि यही पानी पाइपलाइन के जरिए घरों के नलों तक पहुंच रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला पंचायत सदस्य उर्मिला गव्हाड़े ने कलेक्टर से शिकायत कर शीघ्र कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों के अनुसार ग्राम पंचायत हिवरखेड में पाइपलाइन बिछाने का कार्य धीमी गति से चल रहा है। गांव के भीतर जगह-जगह वाल के लिए गड्ढे खोदे गए हैं, लेकिन उन्हें खुला छोड़ दिया गया है। इन गड्ढों में नालियों का गंदा और बदबूदार पानी जमा हो रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि यही दूषित पानी पाइपलाइन में मिलकर घरों तक पहुंच रहा है, जिससे बीमारी फैलने की आशंका बढ़ गई है। ग्रामीण कचरा घोटे ने बताया कि होली चौक स्थित उनके घर के पास पिछले एक माह से गड्ढा खोदा हुआ है। उस गड्ढे में लगे वाल के आसपास गंदा पानी भरा रहता है और वही पानी घरों के नलों में पहुंच रहा है। उन्होंने बताया कि गड्ढा गहरा और लंबा होने के कारण रात में दुर्घटनाएं हो रही हैं और छोटे बच्चों के गिरने का डर बना रहता है।

- बार-बार सूचना, फिर भी नहीं हुई कार्रवाई

ग्रामीणों ने बताया कि पीएचई विभाग के इंजीनियर और संबंधित ठेकेदार को कई बार इस समस्या से अवगत कराया गया, लेकिन किसी ने गंभीरता नहीं दिखाई। लगातार अनदेखी के बाद गांव के विभिन्न मोहल्लों के लोग शिकायत लेकर जिला पंचायत सदस्य उर्मिला गव्हाड़े के पास पहुंचे। जिला पंचायत सदस्य उर्मिला गव्हाड़े ग्रामीणों के साथ मौके पर पहुंचीं और स्थिति का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि गांव में जगह-जगह खोदे गए गड्ढों में गंदा पानी जमा है और वही पानी नलों के माध्यम से घरों में पीने के लिए पहुंच रहा है, जिससे लोग बीमार हो सकते हैं। उन्होंने पीएचई विभाग के ई ई बघेल को भी अवगत कराया, लेकिन जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो कलेक्टर को शिकायत कर तत्काल हस्तक्षेप की मांग की, ताकि ग्रामीणों को स्वच्छ पेयजल मिल सके और संभावित स्वास्थ्य संकट को रोका जा सके।

परामर्शदात्री समिति की बैठक में प्राप्त सुझावों पर किया जायेगा अमल - ऊर्जा मंत्री श्री तोमर

भोपाल ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि विभागीय परामर्शदात्री समिति की बैठक में सदस्यों द्वारा दिये गये सुझावों पर अधिकारी 5 दिवस में रिपोर्ट तैयार करें। साथ ही प्राप्त सुझावों पर गंभीरता से विचार कर अमल में लाने के प्रयास किये जायेंगे। श्री तोमर ने कहा मध्यप्रदेश में पर्याप्त बिजली उपलब्ध है। उद्योगों से लेकर किसानों तक सभी को पर्याप्त विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है। बैठक में समिति के सदस्यों ने महत्वपूर्ण सुझाव दिये। उन्होंने कहा कि वन क्षेत्र में जंगली जानवरों से खतरे के मद्देनजर सिंचाई के लिये दिन में ही विद्युत आपूर्ति करने पर विचार किया जाये। इस दौरान सचिव श्री विशेष गढ़पाले ने विभाग की 2 वर्ष की उपलब्धियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश पॉवर ट्रांसमिशन कंपनी की हानियां वर्ष 2024-25 में 2.60 प्रतिशत रहीं, जो न्यूनतम में से एक है। अमरकंटक विद्युत गृह द्वारा कंपनी के इतिहास में अब तक सर्वाधिक 512 दिन तक लगातार विद्युत उत्पादन किया गया। बिजली कंपनियों की उपभोक्ता सेवाओं में सुधार के लिये लगभग 52 हजार स्थायी पदों का सृजन किया गया है। भर्ती प्रक्रिया चालू कर दी गई है। प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाभियान अंतर्गत जनजातीय समुदाय के 26 हजार 909 घरों को विद्युतीकृत किया गया है। स्मार्ट मीटरिंग के माध्यम से प्री-पेड उपभोक्ताओं को ऊर्जा प्रभार में 25 पैसे प्रति यूनिट की छूट दी जा रही है। उन्होंने विभिन्न नवाचारों के बारे में भी जानकारी दी। बैठक में समिति के सदस्य विधायक श्री यादवेन्द्र सिंह, श्री गौरव सिंह पारधी, श्री ठाकुर दास नागवंशी, श्री घनश्याम चंद्रवंशी और श्री सुरेन्द्र सिंह बघेल एवं अधिकारी उपस्थित थे।

हर बूंद की रखवाली पांढरा गांव में एनएसएस शिविर बना जल संरक्षण की जीवंत पाठशाला

नदी पर बोरी बंधान कर स्वयंसेवकों ने दिया संदेश वर्षा जल संचयन और सामुदायिक प्रयास ही भविष्य के जल संकट का समाधान

सारनी।जल ही जीवन है इस संदेश को व्यवहार में उतारते हुए पांढरा गांव में आयोजित राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) के सात दिवसीय शिविर के पाँचवें दिन स्वयंसेवकों ने नदी पर बोरी बंधान निर्माण कर जल संरक्षण की अनूठी मिसाल पेश की।श्रमदान के माध्यम से किए गए इस कार्य ने न केवल जल बचाने का संदेश दिया,बल्कि ग्रामीणों को स्थानीय संसाधनों से जल संकट का समाधान खोजने की प्रेरणा भी दी।बोरी बंधान एक पारंपरिक और प्रभावी जल संरक्षण तकनीक है, जिसके माध्यम से बहते पानी की गति को नियंत्रित कर उसे रोका जाता है,जिससे भूजल स्तर बढ़ता है और आसपास के खेतों व कुओं में पानी की उपलब्धता लंबे समय तक बनी रहती है।स्वयंसेवकों ने ग्रामीणों को बताया कि वर्षा जल का संरक्षण भविष्य की सबसे बड़ी जरूरत बन चुका है,क्योंकि लगातार घटते जलस्तर और अनियमित बारिश ग्रामीण जीवन के लिए चुनौती बन रहे हैं।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जनभागीदारी समिति अध्यक्ष कमलेश सिंह,सारनी नगर पालिका अध्यक्ष किशोर बार्डे,बासपुर हाई स्कूल के प्रधान पाठक मंसुलाल आहाके तथा शिक्षक त्रिभुवन वर्मा उपस्थित रहे।अतिथियों का स्वागत स्वयंसेवकों द्वारा पुष्पगुच्छ भेंट कर किया गया।यह शिविर वीर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सरदार विष्णु सिंह उइके शासकीय महाविद्यालय,सारनी के तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है।कार्यक्रम की शुरुआत स्वयंसेविका किरण द्वारा तैयार शिविर दर्पण के उद्घाटन से हुई।मुख्य अतिथि कमलेश सिंह ने स्वयंसेवकों के श्रम और नवाचार की सराहना करते हुए कहा कि छोटे-छोटे प्रयास ही बड़े जल आंदोलन का आधार बनते हैं।वहीं नगर पालिका अध्यक्ष किशोर बरदे ने विद्यार्थियों को दैनिक जीवन में जल बचाने के व्यावहारिक उपाय अपनाने की प्रेरणा दी। मंसुलाल आहाके ने जल संरक्षण को आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से जोड़ते हुए इसकी आवश्यकता पर प्रकाश डाला।बोरी बंधान निर्माण कार्य में अमन कश्यप,दुर्गेश वरकड़े,कैलाश कोलांकर,शुभम गुप्ता,अभय साहू,गौतम भोरस,तरुण साहू,आयुष सरियाम,उत्तम धुर्वे,पूजा भोरसे,शीतल, काजल,तरुणा,अनुष्का, अंकिता,लता,सुगवती, दीपिका,पूर्णिमा,लक्ष्मी,हर्षा, सोनम,वैष्णवी,सपना एवं तनुश्री सहित सभी स्वयंसेवकों ने सक्रिय भागीदारी निभाते हुए सामूहिक श्रम से निर्माण कार्य को सफल बनाया। महाविद्यालय के प्राचार्य प्रदीप पंद्राम सहित स्टाफ सदस्य अंजना राठौर,लक्ष्मी नागले,सविता पटेल,अनीता नागले,कविता महाले,संगीता उघड़े,गोलमन आहाके, मनोज नागले,मोहन पवार, शैलेश श्रीवास्तव,उत्तम साहू, अनुज हलदार एवं अनिल तुमडाम भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। प्राचार्य पंद्राम ने बच्चों एवं ग्रामीणों को जल की उपयोगिता,वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण के सरल उपायों की जानकारी देते हुए कहा कि पानी बचाना केवल जिम्मेदारी नहीं,बल्कि आने वाले कल को सुरक्षित करने का संकल्प है।इसी संदेश के साथ कार्यक्रम का सफल समापन किया गया ।

घर के भीतर अवैध सागौन का गुप्त कारखाना, वन विभाग की दबिश में खुला राज, 45 नग चिरान जब्त

करीब 35 हजार रुपये मूल्य की सागवान बरामद, प्रकरण दर्ज, ताप्ती रेंज की कार्रवाई

बैतूल। वन विभाग ने अवैध सागौन लकड़ी के कारोबार पर सख्त कार्रवाई करते हुए ताप्ती रेंज के मोहुपानी सर्किल अंतर्गत ग्राम गोनीघाट में एक घर से बड़ी मात्रा में सागवान चिरान जप्त की है। यह कार्रवाई 26 फरवरी को बन मंडल अधिकारी दक्षिण बैतूल अरिहंत कोचर के निर्देशन एवं उप वनमण्डल अधिकारी आमला देवानंद पाण्डेय के मार्गदर्शन में की गई। वन विभाग की टीम ने जयराम यादव के घर पर दबिश दी, जहां अवैध रूप से फर्नीचर निर्माण का कार्य किया जा रहा था। मौके से 45 नग सागौन चिरान, कुल 0.431 घन मीटर लकड़ी जप्त की गई। जप्त लकड़ी का अनुमानित बाजार मूल्य लगभग 35 हजार रुपये बताया गया है।

- दो अलग-अलग अधिनियमों की धाराओं में दर्ज हुआ प्रकरण

मामले में जयराम यादव के खिलाफ पीओआर क्रमांक 266/45 दर्ज किया गया है। प्रकरण भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 26(1)क तथा मध्य प्रदेश वन उपज व्यापार विनिमय अधिनियम 1969 की धारा 5(1) के तहत कायम किया गया है। वन विभाग ने स्पष्ट किया है कि अवैध रूप से वन उपज का उपयोग और व्यापार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

- कार्रवाई में रेंज स्टाफ की सक्रिय भूमिका

इस पूरी कार्रवाई में रेंज ऑफिसर दयानन्द डेहरिया, ओंकारनाथ मालवीय, रमेश मस्की परिक्षेत्र सहायक, भैया लाल कुमरे, कामुलाल इवने, दीप्ति राजपूत और सोनू पुंडे की सक्रिय भूमिका रही। वन विभाग ने क्षेत्र में अवैध लकड़ी कटाई और उपयोग पर लगातार निगरानी बनाए रखने की बात कही है।

उक्त जानकारी मीडिया प्रतिनिधियों को सूचनार्थ प्रेषित की गई है।
विस्तृत जानकारी के लिए संपर्क करें 82259 14141

बोर्ड परीक्षाओं के बीच ध्वनि प्रदूषण का शोर छात्रों की पढ़ाई पर भारी पड़ रहे डीजे और लाउडस्पीकर

प्रशासन की अनुमति और ढिलाई पर उठे सवाल, शहरी-ग्रामीण क्षेत्रों में तेज आवाज से परीक्षार्थी परेशान

सारनी।वर्तमान समय में वार्षिक परीक्षाओं का दौर जारी है।कक्षा आठवीं,दसवीं और बारहवीं की एमपी बोर्ड तथा सीबीएसई परीक्षाएं चल रही हैं,ऐसे महत्वपूर्ण समय में विद्यार्थियों के लिए शांत वातावरण अत्यंत आवश्यक माना जाता है।इसके बाद भी शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न सामाजिक,धार्मिक एवं वैवाहिक कार्यक्रमों में तेज आवाज वाले डीजे, लाउडस्पीकर और साउंड सिस्टम का उपयोग लगातार किया जा रहा है,जिससे परीक्षार्थियों को गंभीर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।स्थिति चिंताजनक तब हो जाती है जब स्थानीय पुलिस प्रशासन कार्यक्रमों में तेज ध्वनि व्यवस्था को देखे जाने के बाद भी कोई प्रभावी कार्रवाई करता नजर नहीं आता।वहीं राजस्व विभाग के जिम्मेदार अधिकारी तहसीलदार एवं एसडीएम को भी परीक्षाओं के चलने की जानकारी होने के बाद कई कार्यक्रमों में साउंड सिस्टम की अनुमति दिए जाने के आरोप सामने आ रहे हैं।शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के अनेक विद्यार्थियों और अभिभावकों का कहना है कि देर रात तक बजने वाले डीजे और तेज ध्वनि उनके अध्ययन में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। कई मामलों में जब स्थानीय लोग या अभिभावक कार्यक्रम आयोजकों से आवाज कम करने का अनुरोध करते हैं,तो विवाद और मारपीट जैसी स्थिति तक बन जाती है,जिससे सामाजिक तनाव भी बढ़ रहा है।ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए नागरिकों ने जिला प्रशासन से मांग की है कि परीक्षा अवधि के दौरान धार्मिक,सामाजिक एवं वैवाहिक कार्यक्रमों में तेज ध्वनि वाले साउंड सिस्टम और डीजे पर सख्त नियंत्रण लगाया जाए। साथ ही बिना शासकीय अनुमति के संचालित हो रहे साउंड सिस्टम पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाए,ताकि विद्यार्थियों को शांत और अनुकूल वातावरण मिल सके।परीक्षाएं विद्यार्थियों के भविष्य से जुड़ी होती हैं,ऐसे में प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि नियमों का कड़ाई से पालन कराते हुए ध्वनि प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया जाए, जिससे शिक्षा और अनुशासन दोनों की गरिमा बनी रहे।

सारनी में गूंजा क्रिकेट का रोमांच

हाईस्कूल प्रीमियर लीग का भव्य शुभारंभ,प्रदेश स्तरीय मुकाबलों में युवा खिलाड़ियों का जलवा

सारनी। खेल प्रतिभाओं को मंच देने और युवाओं में खेल भावना को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सारनी शहर में आयोजित तीन दिवसीय हाईस्कूल प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता का गुरुवार को भव्य शुभारंभ हुआ। आयोजक समिति के पदाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि 27 फरवरी से 1 मार्च तक चलने वाली इस प्रदेश स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता में रोमांच, प्रतिस्पर्धा और खेल उत्साह का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है।आईपीएल की तर्ज पर आयोजित इस टूर्नामेंट में कुल 6 टीमों ने भाग लिया है,जिनके बीच 15 रोमांचक मुकाबले खेले जाएंगे।उद्घाटन समारोह में खेल प्रेमियों और स्थानीय नागरिकों की उत्साहपूर्ण उपस्थिति ने आयोजन को यादगार बना दिया।कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथियों प्रदेश कांग्रेस डेलीगेट तिरुपति एरोलू,भाजपा मंडल उपाध्यक्ष मुकेश यादव,यूथ कांग्रेस प्रदेश महासचिव सन्नी अरोलू,पूर्व यूथ कांग्रेस अध्यक्ष हेमंत धोटे तथा यमल शर्मा द्वारा पूजा-अर्चना एवं रिबन काटकर किया गया। पहले दिन के मुकाबले रहे बेहद रोमांचक प्रतियोगिता का उद्घाटन मैच दामाडे लायन और द लाइंस किंग के बीच खेला गया,जिसमें शानदार प्रदर्शन करते हुए द लाइंस किंग ने जीत दर्ज की। इसके बाद खेले गए मुकाबलों में रेड डायमंड ने सतपुड़ा टाइगर को हराकर जीत हासिल की।थंडर स्ट्राइकर ने वेदांत इलेवन के खिलाफ एकतरफा जीत दर्ज की।दिन का सबसे रोमांचक मुकाबला दामाडे लायन बनाम सतपुड़ा टाइगर के बीच रहा,जो टाई होने के बाद सुपर ओवर तक पहुंचा,जहां दामाडे लायन ने बाजी मार ली।दिन का अंतिम मुकाबला द लाइंस किंग और थंडर स्ट्राइकर के बीच खेला जा रहा है,जिसे लेकर दर्शकों में खासा उत्साह बना हुआ है।प्रतियोगिता को सफल बनाने में आयोजन समिति के सदस्य लखबीर डोंगरे,महेश डोंगरे,हेमंत धोटे,रवि कौशिक,राजेश मालवीय, साजिद खान,हितेन सिंदूर, रवि सिंदूर,गुलशन डोंगरे, अरुण बंछोर,गगन,राधे चौकीकर,सावन सिंदूर, अजय नागले,हर्ष,बंटी,संतु, गगन भौरपी,शफात खान, शक्ति सिंदूर,विक्की मालवीय,मनीष चंद्रवंशी, हितेश सिंदूर,शैलेश भूमरकर, साहिल,संदीप ध्रुवे सहित अन्य सदस्यों का महत्वपूर्ण सहयोग रहा।आयोजकों ने बताया कि इस प्रतियोगिता का उद्देश्य ग्रामीण एवं अंचल के युवा खिलाड़ियों को प्रदेश स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर प्रदान करना है,ताकि भविष्य में वे बड़े मंचों तक पहुंच सकें।

ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग की 28 फरवरी को रैली:यूजीसी कानून के समर्थन में आयोजन, ज्ञापन सौंपकर रखेंगे आठ मांगें

प्रतिनिधियों ने कहा कि वे यूजीसी के प्रावधानों को लागू रखने के पक्ष में हैं, लेकिन यदि किसी वर्ग का नुकसान हो रहा है तो उसमें सुधार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग की जनसंख्या अधिक है, फिर भी उन्हें उसी अनुपात में लाभ नहीं मिल रहा है। ओबीसी वर्ग के 27 प्रतिशत आरक्षण पर लगी रोक का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया जाएगा। उनका कहना है कि इससे बड़ी संख्या में छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ है।

अशोकनगर संवाददाता

अशोकनगर में ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग द्वारा 28 फरवरी को एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। यह आयोजन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के समर्थन और विभिन्न सामाजिक मांगों को लेकर किया जा रहा है। पछाड़ी खेड़ा में सभा के बाद रैली निकाली जाएगी। इसके बाद तीनों वर्गों के प्रतिनिधि अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपेंगे। कार्यक्रम को लेकर बुधवार शाम राजश्री होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इसमें विभिन्न समाजों के प्रतिनिधियों ने कार्यक्रम की रूपरेखा और उद्देश्यों की जानकारी दी।

आरक्षण और अधिकारों का मुद्दा उठाएंगे

प्रतिनिधियों ने कहा कि वे यूजीसी के प्रावधानों को लागू रखने के पक्ष में हैं, लेकिन यदि किसी वर्ग का नुकसान हो रहा है तो उसमें सुधार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग की जनसंख्या अधिक है, फिर भी उन्हें उसी अनुपात में लाभ नहीं मिल रहा है। ओबीसी वर्ग के 27 प्रतिशत आरक्षण पर लगी रोक का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया जाएगा। उनका कहना है कि इससे बड़ी संख्या में छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ है। आयोजन में जातिगत जनगणना कराने, ओबीसी वर्ग को विधानसभा और लोकसभा सीटों में आरक्षण देने सहित कुल आठ मांगें रखी जाएंगी। 52 प्रतिशत आरक्षण का मुद्दा भी ज्ञापन में शामिल रहेगा। यह कार्यक्रम दीनाभाना जयंती के अवसर पर किया जा रहा है। कार्यक्रम की शुरुआत उनके छायाचित्र पर श्रद्धांजलि अर्पित कर की जाएगी, इसके बाद सभा और रैली का आयोजन होगा।

सिर्फ 10 मिनट में साफ होगा पूरा बाथरूम

बाथरूम धोने का काम यदि किसी को सिरदर्द लगता है, तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। दरअसल, इस एरिया में जमी गंदगी आमतौर पर इतनी जिद्दी होती है, कि इसे साफ करने में पसीना निकल आता है। इसलिए आमतौर पर लोग बाथरूम की सफाई के नाम पर सिर्फ टॉयलेट सीट को ही साफ करके अपना काम खत्म मान लेते हैं। लेकिन जब घर में खास मेहमान आने वाले हो तो यह कामचोरी नहीं चल पाती है। और फिर घंटो तक इसके कोने-कोने को चमकाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है।ऐसे में आज हम आपके लिए ऐसा जबरदस्त ट्रिक लेकर आए हैं, जिससे आप सिर्फ 10 मिनट में अपने बाथरूम के हर एक कोने को चमका सकते हैं, वो भी कम मेहनत में। इसकी मदद से बाथरूम को मेहमानों के लिए एवरेडी बनाकर रखना भी आसान होता है।सबसे पहले करें ये कामकम समय में बाथरूम साफ करना हो तो सबसे पहले यह देखना जरूरी है, कि किन हिस्सों में ज्यादा गंदगी जमा है। एक बार जब आप इन डर्टी स्पॉट्स की पहचान कर लेते हैं, तो बारी आती है इन्हें साफ करने के लिए सामग्री को एक जगह जमा करने की।इसमें आपके लिए सबसे ज्यादा मददगार साबित होते है- ब्रश,स्क्रबर, माइक्रोफाइबर क्लॉथ, वाइपर, विनेगर, बेकिंग सोडा और टॉयलेट क्लीनर,

ट्राई करें ये तरीका चमक उठेगा का कोना-कोना

डिटर्जेंट। इसके साथ ही फर्श पर रखे सभी सामान और नॉब पर टंगे सभी कपड़ों बाहर निकालकर बाथरूम को जितना हो सके खाली कर लें।बाथरूम में करें क्लीनर का छिड़कावजैसे ही आप बाथरूम में सफाई के लिए जाते हैं, सबसे पहले हर जगह क्लीनर लिक्विड का छिड़काव कर दें। इसे आप डिटर्जेंट, विनेगर और बेकिंग सोडा को बराबर मात्रा में पानी में मिलाकर तैयार कर सकते हैं।इससे आपको गंदगी को हटाने में ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी और बाथरूम की बदबू भी गायब हो जाएगी। इसके साथ ही टॉयलेट क्लीनर को भी पॉट में अच्छे से सब तरफ लगाकर छोड़ दें।टैब को करें साफअब जब तक ये क्लीनर गंदगी को ढीला करने का काम कर रहा है, आप माइक्रोफाइबर क्लॉथ से वॉटर टैब और शावर हैड को क्लीन कर लें। ऐसा करने से इसपर बने पानी के सारे दाग मिट जाएंगे। यदि इस पर जंग के दाग बन गए हैं, तो उन्हें हटाने के लिए विनेगर बेकिंग सोडा से तैयार क्लीनर को इसपर लगाकर स्क्रबर से रगड़कर

साफ करें। इसमें मुश्किल से आपको 2-3 मिनट लगेगा।टाइल्स को करें साफइतने समय में टाइल्स पर डाला हुआ क्लीनर अपना काम कर चुका होगा, तो आप स्क्रबर से रगड़कर इन्हें साफ पानी से धो लें। फर्श को भी इसी तरह से साफ कर लें। साथ ही अगर बाथरूम में शीशा लगा हुआ है, तो इसे माइक्रोफाइबर क्लॉथ से साफ कर लें।टॉयलेट को क्लीन करेंसबसे अंत में टॉयलेट को क्लीन करें। क्योंकि इसमें जमी गंदगी बहुत सख्त होती है, जिसे सॉफ्ट होने में टाइम लगता है। ब्रश से रगड़कर इसे साफ कर लें। और इसे फ्लश करके धोने की जगह जेट स्प्रे का इस्तेमाल करें इससे आसानी से सारा क्लीनर निकल जाता है। ऐसे में आपका बाथरूम 10 मिनट में पूरी तरह से चमकता नजर आने लगेगा।

इस खराबी के कारण आने लगती हैं से तेज आवाजें

जून के महीने में गर्मी से राहत पाने के लिए एयर कंडीशनर से बेहतर कुछ नहीं होता। लेकिन जब आप एसी की ठंडक में सुकून भरी नींद ले रहे हों और इस दौरान इससे तेज आवाज आने लगे तो पूरा दिमाग खराब हो जाता है। नींद में भी यह चिंता सताने लगती है, कि अचानक से एसी को क्या हो गया है। यदि आपके एयर कंडीशनर

भूल से भी न करें इंग्रोर जानें घर पर ठीक करने के उपाय

के साथ भी इस तरह की समस्या आ रही है, तो यह लेख आपके लिए है।एसी से आने वाली अजीब और तेज आवाजें इसमें चल रही गड़बड़ी का नतीजा होती है। इसलिए इसे कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। क्योंकि कई बार यह आवाजें कुछ ऐसी समस्याओं का संकेत होती है, जिन्हें तुरंत ठीक करना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो एयर कंडीशनर खराब भी हो जाता है। ऐसे में जब आपका एसी शोर करना शुरू करे, तो इसे फिर से सुचारू रूप से चलाने के लिए यहां बताए कुछ सुधारों को आजमा सकते हैं। लेकिन यदि इससे कोई फायदा न दिखे तो आपको एक्सपर्ट को बुलाने की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन इससे पहले जान लें कि एसी से अचानक इतना शोर कैसे शुरू हो जाता है, इसका कारण कौन-कौन सी चीजें होती हैं।क्यों आती है एसी से तेज आवाजएसी के पुराने होने के कारणमशीन के पार्ट्स लूज होने सेएसी के हिस्सों में कचरा-डस्ट भर जानारेफ्रीजरेंट लीक होने परएसी के पार्ट्स जाम होने सेकंप्रेसर और कंडेनसर की जांच करेंकंप्रेसर और कंडेनसर की जांच करेंएयर कंडीशनर से आवाज आने पर इसका कंप्रेसर और कंडेनसर जांचे।यदि एसी 10 साल या उससे अधिक पुराना है, तो यह पार्टस शोर का कारण हो सकते हैं।इसके साथ ही एसी से तेज भिनभिनाहट की आवाज आती है, तो यह मोटर के खराब होने का संकेत हो सकता है। ऐसे में इसे बदलने के लिए या रिपेयर करने के लिए आपको एक्सपर्ट की आवश्यकता होती है।ढीले पार्ट्स को टाइट करेंढीले पार्ट्स को टाइट करेंअपने कंडेनसर के स्क्रू पर करीब से नज़र डालें।

घर की दीवारों पर कौन-सा रंग लगेगा सही, नहीं आ रहा समझ तो ऐसे चुनें कमरे का कलर डिजाइन

घर की बनावट भले ही कितना भी यूनिक हो लेकिन यह खूबसूरत तब तक नहीं नजर आता है, जब तक इसमें रंग न भरे जाए। कलर की मदद से हर एक दीवार घर की सुंदरता में चार चांद लगा सकती है। लेकिन ज्यादातर लोग कलर की इस अहमियत को बहुत हल्के में लेते हैं। जिसका नजीता यह होता है, कि लाखों-करोड़ों में तैयार घर भी अच्छा नजर नहीं आता है।वैसे तो हर रंग की अपनी एक खूबसूरती है, लेकिन घर की किस दीवार पर कौन-सा रंग ज्यादा अच्छा लगेगा यह चुनना बहुत कठिन काम होता है। कई लोग तो रंग चुनने की मेहनत से बचने के लिए सबसे ज्यादा पॉपुलर होम कलर डिजाइन ट्रेंड और कॉम्बिनेशन को ही बिना सोचे समझे कॉपी कर लेते हैं, जिसका रिजल्ट कई बार बहुत निराशाजनक भी होता है। ऐसे में यहां हम आज आपको घर के लिए सही कलर पैलेट चुनने का सबसे आसान तरीका बता रहे हैं। इसकी मदद से आप कम लग्जरी सामानों से भी अपने घर को लेविश लुक दे सकते हैं।फर्नीचर से मैच करें दीवारों का कलररूम को पेंट करने के लिए कलर चुनना हो तो सबसे आसान तरीका है, अपने घर के फर्नीचर के रंगों को ध्यान से देखें। इसमें आपके सोफा से लेकर कूशन और टेबल लैंप तक सब आते हैं। अब यदि इनका कलर डार्क है, तो दीवारों के लिए लाइट कलर चुनें, और यदि यह लाइट कलर में है, तो दीवारों को डार्क रंग से पेंट करें। ऐसा करने से फर्नीचर निखरकर नजर आते हैं, जो

इंटीरियर की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए जरूरी है।कमरे के साइज के अनुसार चुने रंगरूम का साइज और इसकी दीवारों का कलर एक-दूसरे को बहुत इफेक्ट करता है। इसलिए जरूरी होता है, घर को पेंट करने से पहले इसके साइज को अच्छी तरह से चेक कर लेना चाहिए।यदि रूम छोटा है, तो इसमें डार्क कलर का पेंट करना बहुत बेकार आइडिया होता है, क्योंकि इससे रूम और भी छोटा नजर आने लगता है। ऐसे में छोटे साइज के रूम के लिए लाइट शेड का इस्तेमाल करें।कलर रूल का रखें ध्यानघर की दीवारों के लिए जब कलर चुनना हो तो 60 30 10 के कलर रूल को कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। यह एक क्लासिक डेकोर रूल है, जो आपके स्पेस के लिए कलर पैलेट को क्रिएट करने में मदद करता है।यह नियम दर्शाता है, कि रूम का 60 प्रतिशत डोमिनेंट या डार्क कलर में होना चाहिए, 30 प्रतिशत में सेकेंडरी कलर या टेस्चर होना चाहिए और 10 प्रतिशत में डोमिनेंट कलर का कंट्रास्ट या कॉम्प्लिमेंट कलर होना चाहिए।

नहीं जम रहा फ्रीजर में रखे आईस ट्रे का पानी जानें कारण और की इस गड़बड़ी को घर में ठीक करने के उपाय

फ्रिज का इस्तेमाल लगभग हर घर में होता है। गर्मी के दिनों में पानी को ठंडा रखने से लेकर भोजन को फ्रेश रखने तक का काम इसकी वजह से बहुत आसान होता है। घरों में इस मौसम में हजारों बार फ्रिज को खोला और बंद किया जाता है। हो भी क्यों न आईस क्यूब से लेकर खानपान की लगभग हर चीज फ्रीज में ही जो रखी हुई मिलती है। अब ऐसे में यदि इसका फ्रीजर ठीक से काम न करे तो बहुत मुश्किल हो जाती है।वैसे तो एक रेफ्रिजरेटर और इसका फ्रीजर आराम से 10 से 15 साल तक सही से चल सकता है। इतना समय बीतने के बाद किसी भी तरह की प्रॉब्लम इस बात का संकेत होती है, कि आपको नए फ्रिज की जरूरत है। लेकिन ज्यादा पुराना न होने पर यदि उसमें बर्फ ज्यादा जमने या न जमने की परेशानी हो तो इसे तुरंत ठीक करने के उपाय करना बेहतर होता है। क्योंकि कई बार यह आपके लापरवाही और फ्रिज के गलत रखरखाव के कारण भी होता है, ऐसे में इसे सही करने का तरीका पता होने से आप इसे फ्री में घर पर ही सही कर सकते हैं। यहां आप फ्रीजर के सही तरह से ठंडा नहीं करने के ऐसे ही कारणों से बारे में जान सकते हैं।फ्रीजर में फ्रॉस्ट बिल्डअप हो सकती है वजहफ्रीजर की दीवारों पर ज्यादा फ्रॉस्ट जमने से उसको ठंडा करने वाले वेंट और कॉइल बंद हो जाते हैं। ऐसे में यदि आपका फ्रीजर काम नहीं कर रहा है, तो जमी हुई बर्फ को तोड़कर जमाव को हटाकर हाई टेंपरेचर पर फ्रिज का रेगुलेटर सेट करें।यह ध्यान रखें कि हाई टेक फ्रीजर में

ऑटो डिफ्रॉस्ट की सुविधा होता ही, ऐसे में ज्यादा फ्रॉस्ट बिल्डअप होने पर इन्हें बदलने की आवश्यकता होती है। जिसके लिए आपको मैकेनिक की जरूरत पड़ सकती है।कंडेनसर कॉइल्स का गंदा होनायदि आपका फ्रीजर बर्फ जमा नहीं रहा है, तो कंडेनसर कॉइल का गंदा होना इसका कारण हो सकता है। दरअसल, जब कॉइल का रखरखाव ठीक से नहीं किया जाता है, तो यह आपके फ्रीजर की कूलिंग क्षमता को कम कर देता है। ऐसे में कंडेनसर कॉइल को साफ करने के लिए आप कॉइल को वैक्यूम कर सकते हैं, या फिर एक ब्रश की सहायता से इसे साफ कर सकते हैं। लेकिन ऐसा करते हुए ध्यान रखें कि फ्रिज स्विच बोर्ड से अनप्लग हो।खराब हो सकता है फ्रीजर का थर्मोस्टेटयदि आपका फ्रीजर बर्फ नहीं जमा रहा है, तो आप उसके थर्मोस्टेट को चेक करें। आमतौर पर इसमें समस्या होने पर फ्रीजर पर्याप्त ठंडा नहीं कर पाता है। इसे चेक करने के लिए थर्मोस्टेट को निम्नतम से उच्चतम सेटिंग्स में बदलें यदि ऐसा करते हुए क्लिक की आवाज सुनाई नहीं देती है, तो यह खराब हो चुका है और इसे बदलने की आवश्यकता है।फ्रीजर का दरवाजा ठीक से बंद न होनाफ्रीजर का दरवाजा ठीक से बंद न होनाफ्रीजर का गैसकेट दरवाजा बाहर की गर्मी को दूर करके इसमें ठंडक को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी होता है। अगर हर बार बंद करने पर दरवाजा पूरी तरह से बंद नहीं होता है, तो ठंडी हवा बाहर निकल जाता है। जिससे फ्रीजर का तापमान बढ़ने से इसमें बर्फ नहीं जम पाएगी।ऐसे में यह जांचने के लिए कि क्या आपका फ्रीजर दरवाजा ठीक से सील कर रहा है, गैस्केट के सामने पेपर का एक फ्लैट टुकड़ा रखें और दरवाजे को बंद कर दें। फिर, कागज़ को खींच लीजिए। अब यदि कागज का टुकड़ा आसानी से निकल जा रहा है,

सावधान कहीं आपके प्लेट में रखा नकली तो नहीं ऐसे करें शुद्धता की जांच और जानें प्लास्टिक के अंडों का सच

अंडा सेहत के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है। इसकी तासीर गर्म होती है, इसलिए आमतौर पर इसे ठंड के समय में लोग ज्यादा खाते हैं। लेकिन जिन्हें अंडा खाना पसंद हो, वह इसे खाने से पहले मौसम की परवाह नहीं करते हैं। जिम करने वाले ज्यादातर लोग प्रोटीन की पूर्ति के लिए अपने डाइट में अंडों को शामिल करते हैं। लेकिन जरा सोचिए यदि आपके खाने के प्लेट में रखा अंडा नकली हो या इसमें प्लास्टिक मिला हो तो क्या होगाइसमें कोई दो राय नहीं कि नकली फूड को खाने से सेहत पर बुरा असर पड़ता है। किसी भी भोज्य पदार्थ में जरा सी भी मिलावट आपको एक हेल्थ प्रॉब्लम की ओर धकेल सकती है। लेकिन फिर भी मार्केट में कम प्रोडक्शन कोस्ट पर ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए कई सारे खाने-पीने की चीजों की शुद्धता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इससे अंडा भी अछूता नहीं रहा है। ऐसे में अंडे की शुद्धता को कैसे चेक किया जाता है, इसके बारे में पता होना आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है।मार्केट में बिक रहा प्लास्टिक से बना अंडाहाल ही में गाजियाबाद के मोदीनगर में रहने वाले एक निवासी ने अंडे में प्लास्टिक मिले होने की शिकायत प्रशासन से की है। यह पहली बार नहीं जब अंडे की शुद्धता पर सवाल उठाया गया है। बीते सालों में कई बार अंडे के नकली होने की खबर सामने आयी है। लोगों को यह शक अंडे को फोड़ने पर उसमें से निकलने वाले प्लास्टिक जैसी झिल्ली और अजीब सी गंध आने पर हुआ था। तब से अंडे के नकली होने का डर लगभग हर उस व्यक्ति को है, जो इसे खाना पसंद करते हैं।ऐसे चेक करें अंडा असली है या नकलीअंडे को हिलाकर देखें- यदि इसमें से किसी तरह की आवाज आ रही है, तो यह नकली हो सकता है।अंडे को फोड़कर देखें- यदि ऐसा करने पर

पीला और सफेद भाग एक-दूसरे से मिला हुआ है, तो अंडा नकली हो सकता है।पानी के गिलास में डालें अंडा- माना जाता है कि असली होने पर यह पानी में डूब जाता है जबकि नकली अंडा पानी में तैरने लगता है।अंडे को जला कर देखें- यदि यह असली हुआ तो जलाने पर इसपर सिर्फ काला निशान पड़ेगा, जबकि नकली होने पर अंडा जलने लगता है।ने बताया प्लास्टिक से बने अंडों का सचफूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सिरे से इस बात का खंडन किया है, कि मार्केट में प्लास्टिक से बने अंडे बिक रहे हैं। संस्था के अधिकारियों का कहना है, कि अभी तक ऐसी कोई तकनीक नहीं बनी है, जो नकली अंडा बना सके। अंडे से आने वाली बदबू और इसके अंदर से निकलने वाला प्लास्टिक नूमा पदार्थ केवल इसके रखरखाव में गड़बड़ी का नतीजा होता है।क्या अंडे में मिलावट किया जा सकता हैभले ही नकली अंडा बनाना अभी मुमकिन नहीं है, लेकिन इसकी शुद्धता के साथ खिलवाड़ आसानी से किया जा सकता है। 2020 में ही द हिन्दू की रिपोर्ट के अनुसार स्नस्स्ढ्ढ ने कोयंबटूर के दुकानदारों को लेग हॉर्न के अंडे को रंगकर देसी अंडे के रूप में बेचते हुए पकड़ा था। जिसके बाद अधिकारियों ने 3900 अंडों को फोड़कर इसकी ब्रिकी पर रोक लगाने की हिदायत दी थी।ऐसे चेक करें अंडा देसी है कि नहींदेसी अंडा पोल्ट्री अंडों से आकार में छोटा होता है। साथ ही इसकी स्किन भी ज्यादा मुलायम होती है। इसके अलावा इसके रंग की शुद्धता की पहचान करने के लिए आप इसे सूंघ कर देख सकते हैं। यदि इसमें से चाय पत्ती जैसी खुशबू आए तो यह पोल्ट्री अंडा हो सकता है, जिसे रंगकर देसी अंडे के रूप में बेचा जा रहा है।

तो किसान ऐसे चेक करते हैं तरबूज पका है या नहीं

हर मौसम अपने साथ कुछ विशेष तरह के फल और साग-सब्जियां लेकर आता है। जिसके बारे में यह माना जाता है, कि इन्हें इनके मौसम में खाने पर कई सेहतमंद फायदे होते हैं। ऐसे में जब गर्मी का मौसम चल रहा हो, तो तरबूज खाना तो बनता है। लेकिन क्या आपके साथ भी इसे खरीदने में अक्सर धोखा हो जाता है मीठा समझकर क्या आप भी अधपके और बेस्वाद वाले तरबूज ले आते हैं यदि हां तो ये लेख आपके लिए है।तरबूज पका है या नहीं इसे पहचानने का काम भले ही आम लोगों को रॉकेट साइंस लगे, लेकिन इसकी खेती करने वाले किसानों के लिए उल्टे हाथ का काम होता है। वह मिनट भर में भी यह बता देते हैं, कि कौन सा तरबूज अंदर से पूरी तरह लाल है, और कौन सा नहीं। सबसे मजेदार बात तो यह है कि मीठा तरबूज पहचानने की इस ट्रिक को आप भी आसानी से सीख सकते हैं। हम इन्हीं नायाब तरीकों के बारे में यहां आपको बता रहे हैं।तरबूज को खरीदते समय यदि आपने इसके डंठल वाले हिस्से की ओर कभी ध्यान नहीं दिया है, तो अब इसे चेक करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि किसान भी इसी के आधार पर इसके पके होने का पता लगाते हैं।यदि डंठल वाला भाग पूरी तरह से सूखा है तो इसका मतलब है, कि तरबूज पक चुका है। वहीं, अगर यह भाग थोड़ा सा भी फ्रेश दिख रहा है, तो इसका मतलब इसे अच्छे से पकने से पहले ही तोड़

लिया गया है।पके तरबूज पर दिखता है ये कलरयदि आप तरबूज लेने के लिए दुकान पर पहुंच गए हैं, तो सबसे

खरीदने से पहले आप भी जान लें कैसे चुनना चाहिए मीठा

पहले हर एक पीस को उठाकर ये चेक करें कि उसके एक हिस्से पर पीला दाग बना हो। यदि ऐसा कुछ दिख रहा है, तो इसका मतलब तरबूज पका हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिसपर यह पीलापन न हो वह पके हुए नहीं होते हैं, वह बस कम पके तरबूजों की केटेगरी में आते हैं। ध्यान रखें कि यह ट्रिक सिर्फ गहरे हरे रंग वाले तरबूजों के लिए ही होता है।हाथों से थपथपाकर चेक करें तरबूज कितना पका हैहाथों से थपथपाकर चेक करें तरबूज कितना पका हैयदि पहली बार तरबूज खरीदने जा रहे हैं, तो यह तरीका आपको थोड़ा अजीब लग सकता है। लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे पर यह पके तरबूज को पहचानने का सबसे कारगर ट्रिक होता है।तो आपको इसके लिए तरबूज को एक हाथ में उठाकर दूसरे हाथ की हथेलियों से थपथपाना है।

भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा में सांगई के साहिल ने मारी बाजी, तहसील स्तर पर मिला प्रथम स्थान

संवाददाता

गाडरवारा। गायत्री परिवार द्वारा आयोजित भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा में ग्राम सांगई के एकीकृत शासकीय नवीन माध्यमिक शाला के छात्र साहिल कहार ने शानदार सफलता हासिल की है। कक्षा 5वीं के छात्र साहिल ने तहसील स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त कर अपने विद्यालय और गांव का नाम रोशन किया है। इसके साथ ही इसी शाला के कक्षा 5वीं के छात्र दीपक केवट और छात्रा प्रियांसी केवट ने विद्यालय स्तर पर क्रमशः प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। इन सभी प्रतिभावान छात्र-छात्राओं को 1 मार्च को गायत्री शक्तिपीठ में आयोजित भव्य पुरस्कार वितरण समारोह में सम्मानित किया जाएगा। विद्यार्थियों की इस गौरवमयी उपलब्धि पर मार्गदर्शी शिक्षक मधुसूदन पटैल ने उनका उत्साहवर्धन करते हुए सराहना की। इस सफलता पर प्रधानपाठक दशरथ प्रसाद जाटव, राजेश कौरव, विवेक नाईक, देवेंद्र ठाकुर, किरणलता ठाकुर और समस्त स्टाफ ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की है।

सुरक्षा के नाम पर महज शो-पीस बना पुलिस सहायता केंद्र, मदद के लिए 10 किमी भटकने को मजबूर ग्रामीण

संवाददाता

डोभी। ग्रामीणों की सुरक्षा और आपातकालीन स्थिति में तुरंत मदद पहुँचाने के उद्देश्य से लाखों रूपये की लागत से तैयार किया गया डोभी का पुलिस सहायता केंद्र इन दिनों स्वयं अपनी सुरक्षा की गुहार लगा रहा है। शासन की मंशा थी कि इस केंद्र के माध्यम से स्थानीय लोगों को छोटी-बड़ी शिकायतों के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, लेकिन वर्तमान में यह भवन केवल एक शो-पीस बनकर रह गया है, जिस पर अक्सर ताला लटका रहता है। पुलिस सहायता केंद्र पर पुलिसकर्मियों की स्थायी तैनाती न होने के कारण ग्रामीणों में शासन और प्रशासन के विरुद्ध भारी आक्रोश व्याप्त है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि गांव में जब भी कोई आपसी विवाद, लड़ाई-झगड़ा या चोरी जैसी वारदात होती है, तो उन्हें शिकायत दर्ज कराने के लिए 10 किलोमीटर दूर तेंदूखेड़ा थाने के चक्कर लगाने पड़ते हैं। इससे न केवल ग्रामीणों का कीमती समय बर्बाद होता है, बल्कि उन्हें आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पुलिस की सतत अनुपस्थिति के कारण गांव और आसपास के क्षेत्रों में असामाजिक तत्वों की सक्रियता और उनका खौफ बढ़ गया है। कई बार उच्चाधिकारियों से इस संबंध में शिकायत की गई, लेकिन अब तक कोई ठोस सुनवाई नहीं हुई है। डोभी के नागरिकों ने जिला पुलिस अधीक्षक से पुरजोर मांग की है कि इस केंद्र पर जल्द से जल्द पुलिस बल तैनात किया जाए, ताकि क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ हो सके और ग्रामीणों को न्याय के लिए दर-दर न भटकना पड़े।

शिक्षा के मंदिर के पास गरजा प्रशासन का पीला पंजा, भारी विरोध के बीच जमींदोज हुआ अतिक्रमण

संवाददाता

साईंखेड़ा। नगर परिषद साईंखेड़ा के अंतर्गत नवनिर्मित सीएम राइज स्कूल और शासकीय महाविद्यालय के आसपास फैले अवैध अतिक्रमण को प्रशासन ने पूरी तरह जमींदोज कर दिया। मुख्यमंत्री की प्राथमिकता वाले इन शिक्षा प्रोजेक्ट्स के रास्ते में बाधा बन रहे कच्चे-पक्के निर्माणों पर सुबह से ही प्रशासन की जेसीबी गरजने लगी। इस पूरी कार्रवाई के दौरान क्षेत्र में स्थिति काफी तनावपूर्ण बनी रही और स्थानीय निवासियों ने बेदखली का जमकर विरोध भी किया। प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार, स्कूल और कॉलेज के मुख्य मार्ग व सरकारी जमीन पर लंबे समय से कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा था। इस अतिक्रमण के कारण छात्र-छात्राओं को आने-जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था और शिक्षण संस्थानों की बाउंड्री वॉल सहित अन्य विकास कार्य भी बुरी तरह प्रभावित हो रहे थे। राजस्व विभाग और नगर परिषद द्वारा बार-बार नोटिस दिए जाने के बावजूद जब अतिक्रमणकारियों ने कब्जा नहीं हटाया, तो अंततः भारी पुलिस बल की मौजूदगी में यह सख्त कार्रवाई अमल में लाई गई। कार्रवाई के दौरान प्रभावित पक्षों और अधिकारियों के बीच तीखी झड़प भी हुई, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी के कारण स्थिति नियंत्रण से बाहर नहीं हो सकी। प्रशासन ने दो टूक शब्दों में स्पष्ट किया है कि बच्चों के भविष्य और जनहित के कार्यों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप बर्दाशत नहीं किया जाएगा और सरकारी जमीन को मुक्त कराना अनिवार्य था। अतिक्रमण हटने के बाद अब इस क्षेत्र को सुरक्षित कर यहाँ सौंदर्यीकरण और बाउंड्री वॉल निर्माण का कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जाएगा।

रेलवे की सुस्त चाल-5 घंटे की देरी से चल रही विंध्याचल एक्सप्रेस,यात्रियों का धैर्य जवाब दे रहा

संवाददाता

गोटेगांव। गोटेगांव रेलवे स्टेशन पर पिछले काफी समय से विंध्याचल एक्सप्रेस की बिगड़ी चाल यात्रियों के लिए भारी मुसीबत का सबब बन गई है। रेल प्रशासन की अनदेखी के कारण यह ट्रेन अपनी निर्धारित समय सारिणी से घंटों पिछड़ रही है, जिससे यात्रियों में गहरा रोष व्याप्त है। जो ट्रेन नियमानुसार सुबह 7:50 बजे गोटेगांव स्टेशन आनी चाहिए, वह अब प्रतिदिन दोपहर 12:30 बजे के बाद ही पहुँच पा रही है। 4 से 5 घंटे की इस नियमित देरी ने आम नागरिकों और दैनिक यात्रियों का पूरा शेड्यूल बिगाड़ कर रख दिया है।

नौकरीपेशा वर्ग पर आर्थिक और मानसिक मार –

ट्रेन की इस लेटलतीफी का सबसे गंभीर असर उन शिक्षकों और शासकीय कर्मचारियों पर पड़ रहा है जो प्रतिदिन अपनी सेवाओं के लिए दूसरे शहरों का सफर तय करते हैं। दफ्तर और शिक्षण संस्थानों में समय पर न पहुँच पाने के कारण इन कर्मचारियों को न केवल उच्च अधिकारियों की नाराजगी झेलनी पड़ रही है, बल्कि वेतन कटौती की मार भी सहनी पड़ रही है। यही स्थिति प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोगों की भी है, जिनकी नौकरी पर संकट मंडराने लगा है।

स्टेशन पर सुविधाओं का अभाव और सूचनाओं की कमी

स्टेशन पर ट्रेन के आने का सही समय पता न चल पाने के कारण बुजुर्गों, महिलाओं और छोटे बच्चों को कड़कड़ाती धूप और प्लेटफॉर्म की अव्यवस्थाओं के बीच घंटों भूखे-प्यासे बैठकर इंतजार करना पड़ता है। सूचना तंत्र की विफलता के कारण यात्रियों को यह भी पता नहीं चलता कि ट्रेन कितनी और देरी से आएगी।

रेल प्रशासन से समय सुधारने की मांग –

शहर के विभिन्न सामाजिक संगठनों और प्रबुद्ध नागरिकों ने रेल प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों से इस समस्या की ओर ध्यान देने की पुरजोर मांग की है। लोगों का कहना है कि विंध्याचल एक्सप्रेस जैसी महत्वपूर्ण ट्रेन का समय सुधारा जाना जनहित में अनिवार्य है, ताकि क्षेत्र के हजारों यात्रियों को इस रोज-रोज की परेशानी और मानसिक प्रताड़ना से छुटकारा मिल सके।

नौरादेही विस्थापन की बाधाएं होंगी दूर,कलेक्टर ने मलकुही और ढाना में चौपाल लगाकर सुनीं समस्याएं

संवाददाता

नरसिंहपुर। नौरादेही अभयारण्य के अंतर्गत आने वाले ग्रामों के विस्थापन की प्रक्रिया को गति देने के लिए कलेक्टर श्रीमती रजनी सिंह ने शुक्रवार को विकासखंड नरसिंहपुर के ग्राम मलकुही एवं ढाना में विशेष चौपाल का आयोजन किया। इस दौरान कलेक्टर ने ग्रामीणों के बीच बैठकर विस्थापन से संबंधित दावा-आपत्तियों की स्वयं सुनवाई की और उनके प्रकरणों के त्वरित निराकरण के निर्देश दिए।

मलकुही में 12 प्रकरण मौके पर ही पात्र घोषित

ग्राम मलकुही में आयोजित चौपाल के दौरान विस्थापन से जुड़े विभिन्न आवेदनों की सूक्ष्मता से जांच की गई। कलेक्टर ने मौके पर ही 12 प्रकरणों को पात्र घोषित कर दिया, जबकि 7 प्रकरणों में मापदंड पूरे न होने के कारण उन्हें अपात्र पाया गया। शेष बचे अन्य प्रकरणों के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि उनकी जांच जल्द पूरी कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति लाभ से वंचित न रहे।

ढाना में 184 परिवारों को मिला विस्थापन का रास्ता

इसी क्रम में ग्राम ढाना में आयोजित चौपाल में कलेक्टर ने विस्थापन के जटिल मुद्दों पर ग्रामीणों से विस्तार से चर्चा की। यहां बताया गया कि कुल 221 प्रकरणों में से 184 प्रकरण पात्र पाए गए हैं, जबकि 37 प्रकरणों को अपात्र घोषित किया गया है। कलेक्टर ने पात्र परिवारों से आग्रह किया कि वे अपने आवश्यक दस्तावेज जल्द से जल्द प्रस्तुत करें ताकि समयबद्ध तरीके से मुआवजा और विस्थापन की कार्यवाही पूरी की जा सके।

शिक्षा और अनुशासन के केंद्र सरस्वती शिशु मंदिर परिसर का हुआ सीमांकन, भविष्य के विस्तार का मार्ग प्रशस्त

संवाददाता

करकबेल। करकबेल स्थित सरस्वती शिशु मंदिर परिसर की भूमि का विधिवत सीमांकन एवं नाप-जोख का कार्य शुक्रवार, 27 फरवरी 2026 को सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। यह पूरी प्रक्रिया राजस्व विभाग के अमले, विद्या भारती के पदाधिकारियों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की विशेष मौजूदगी में पूरी की गई। विद्यालय प्रबंधन का मानना है कि इस सीमांकन से भूमि संबंधी सरकारी रिकॉर्ड पूरी तरह स्पष्ट हो सकेंगे, जिससे भविष्य में विद्यालय की नवीन शैक्षणिक योजनाओं और बुनियादी ढांचे के विस्तार कार्यों में काफी सुगमता आएगी। इस महत्वपूर्ण राजस्व कार्यवाही के दौरान क्षेत्रीय निरीक्षक देवेंद्र पटेल, पटवारी राकेश साहू और कोटवारों की टीम ने सरकारी दस्तावेजों एवं मानचित्रों के आधार पर भूमि की वास्तविक सीमाओं को सुनिश्चित किया। इस अवसर पर विद्या भारती के जिला सचिव राजकुमार जैन और गोटेगांव शिशु मंदिर के प्रधानाचार्य नर्मदाप्रसाद गुप्ता ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। सीमांकन की प्रक्रिया के दौरान क्षेत्र के प्रतिष्ठित नागरिक और समाजसेवी भी बड़ी संख्या में मौजूद रहे। विद्यालय परिवार और स्थानीय समाजसेवियों की सक्रिय सहभागिता के चलते यह पूरी प्रशासनिक प्रक्रिया शांतिपूर्ण और सुचारू रूप से संपन्न हुई। विद्यालय प्रबंधन ने इस कार्यवाही को संस्थान के व्यवस्थित विकास की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है।

बौछार में श्मशान घाट की भूमि से हटा अवैध कब्जा, प्रशासन की सख्ती देख पीछे हटे अतिक्रमणकारी

संवाददाता

गोटेगांव। जनपद पंचायत गोटेगांव के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत बौछार में शुक्रवार को प्रशासन ने एक बड़ी और प्रभावी कार्रवाई को अंजाम देते हुए श्मशान घाट की भूमि को अतिक्रमण से पूरी तरह मुक्त कराया। लंबे समय से ग्रामीण इस बेशकीमती और सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर अवैध कब्जे की शिकायतें शासन-प्रशासन से कर रहे थे। जनभावनाओं और शासकीय रिकॉर्ड की गंभीरता को देखते हुए तहसीलदार के नेतृत्व में राजस्व विभाग, पंचायत कर्मियों और पुलिस बल की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर बेदखली की कार्यवाही की। कार्यवाही के दौरान तहसीलदार और राजस्व अमले ने पुलिस बल की मौजूदगी में जेसीबी मशीन की मदद से श्मशान भूमि पर किए गए अवैध निर्माण और कब्जों को जमींदोज कर दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण और स्थानीय जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। प्रशासन ने इस सख्त कदम के माध्यम से स्पष्ट संदेश दिया है कि सार्वजनिक हित और श्मशान घाट जैसी संवेदनशील भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विवादित भूमि के मुक्त होने पर ग्रामवासियों ने राहत की सांस ली है और जिला प्रशासन के इस त्वरित निर्णय की सराहना की है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों का कहना है कि वर्षों से लंबित इस समस्या के समाधान होने से अब गांव में अंतिम संस्कार व अन्य धार्मिक व्यवस्थाएं सुचारू रूप से संचालित हो सकेंगी। प्रशासन ने ग्राम पंचायत को निर्देशित किया है कि उक्त भूमि को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं ताकि भविष्य में दोबारा ऐसी स्थिति निर्मित न हो।

डीजीपी श्री कैलाश मकवाणा के मुख्यआतिथ्य में उप पुलिस अधीक्षकों का दीक्षांत समारोह आयोजित

भोपाल

भौंरी स्थित मध्?यप्रदेश पुलिस अकादमी के परेड ग्राउंड में शुक्रवार को मध्यप्रदेश पुलिस के 43 वे बैच के 17परिवीक्षाधीन उप पुलिस अधीक्षकों के दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ। राष्ट्रगीत एवं राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मध्यप्रदेश पुलिस के महानिदेशक श्री कैलाश मकवाणा ने बतौर मुख्य अतिथि सलामी ली। पुलिस महानिदेशक श्री कैलाशमकवाणा ने सभी प्रशिक्षु पुलिस अधिकारियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने प्रशिक्षु अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान समय में पुलिसिंग का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। साइबर अपराधों की बढ़ती चुनौतियों को देखते हुए अधिकारियों को निरंतर साइबर फील्ड में अपनी स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान देना होगा तथा तकनीक और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (ढ्ढ) के उपयोग में दक्ष बनना होगा। श्री मकवाणा ने 'सिंहस्थ 2028' के परिप्रेक्ष्य में आने वाली संभावित सुरक्षा, साइबर एवं संगठित अपराध संबंधी चुनौतियों का उल्लेख करते हुए अधिकारियों से आह्वान किया कि वे भविष्य की परिस्थितियों के अनुरूप स्वयं को तैयार रखें तथा बदलते अपराध परिदृश्य के प्रति सजग एवं सक्षम बनें। उन्होंने कहा कि आज धार्मिक आयोजन से संबंधित या सामुदायिक मुद्दे तथा कानून-व्यवस्था से जुड़ा कोई भी विषयहो , सोशल मीडिया के माध्यम से तुरंत व्यापक रूप ले लेता है। जनता की अपेक्षा रहती है कि पुलिस द्वारा तत्काल और निष्पक्ष कार्रवाई की जाए। अतः प्रत्येक अधिकारी को अपने चरित्र, अनुशासन और निर्णय क्षमता को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि ÷सेवा काल में की गई एक छोटी सी लापरवाही भी पूरे जीवन पर दाग बन सकती है, इसलिए नियमों के अनुरूप ही कार्य करें।÷सोशल मीडिया की सक्रियता के इस दौर में छोटी सी घटना भी वायरल हो सकती है, इसलिए सजगता, संवेदनशीलता और त्वरित प्रतिक्रिया अत्यंत आवश्यक है। डीजीपी ने कहा कि एक अधिकारी में संवेदनशीलता, सुनने की क्षमता तथा तकनीक के प्रभावी उपयोग की योग्यता होनी चाहिए। प्रत्येक अधिकारी को सीखने की प्रवृत्ति बनाए रखते हुए स्वयं को समयानुकूल निरंतर विकसित करते रहना चाहिए। उन्होंने कहा किवर्तमान समय में मादक पदार्थों की समस्या एक गंभीर चुनौती के रूप में सामने आई है, जिसे नियंत्रित करना अत्यंत आवश्यक है। यह केवल अपराध का विषय नहीं, बल्कि समाज और युवाओं के भविष्य से जुड़ा संवेदनशील मुद्दा है। जिस प्रकार संगठित प्रयासों और दृढ़ संकल्प से नक्सल प्रभाव को समाप्त करने की दिशा में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई है, उसी प्रकार नारकोटिक्स के विरुद्ध भी सुनियोजित रणनीति, कड़ी कार्रवाई और सतत अभियान चलाकर इसे जड़ से समाप्त करना समय की आवश्यकता है। उन्होंने अपने 37 साल की पुलिस सेवा के अनुभव से सभी को अवगत कराते हुए बताया कि यदि आप अच्छा कार्य करेंगे वो कहीं न कहींअच्छे कर्म आपकी सहायता करते ही हैं, अतः आप ईमानदारी एवं पूर्ण कर्तव्यनिष्ठा से अपने कार्य को करते हुए एक कुशल पुलिस अधिकारी एवं एक अच्छे नागरिक बनें जिससे कि पुलिस विभाग एवं आपके परिजनों को गर्व की अनुभूति हो। डीजीपी श्री मकवाणा ने अधिकारियों से कहा कि वे अपनी वर्दी पर गर्व करें तथा गरीब, पीड़ित, भयभीत और असहाय लोगों की सहायता को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। दूसरों की सहायता करने में ही वास्तविक आनंद है। उन्होंने कहा कि पुलिस सेवा केवल नौकरी नहीं, बल्कि उत्तरदायित्वपूर्ण सेवा है। इस मार्ग में चुनौतियाँ आएँगी, किन्तु निराश हुए बिना दृढ़ निश्चय, अनुशासन एवं सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना ही सफलता का मूल मंत्र है। अधिकारियों को सदैव एक अच्छा एवं संवेदनशील इंसान बने रहने का प्रयास करना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान 43वें उप पुलिस अधीक्षक बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों ने प्रशिक्षण काल के अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश पुलिस अकादमी, भोपाल में प्राप्त कठोर शारीरिक प्रशिक्षण, विधिक ज्ञान, तकनीकी दक्षता एवं नेतृत्व विकास से उन्हें भविष्य की चुनौतियों का सामना करने हेतु आत्मविश्वास एवं संकल्प शक्ति प्राप्त हुई है। मध्यप्रदेश पुलिस अकादमी के उप निदेशक श्री संजय कुमार अग्रवाल ने प्रशिक्षण का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश पुलिस अकादमी वर्ष 2013 में स्थापित राज्य की शीर्ष प्रशिक्षण संस्था है, जहाँ उप पुलिस अधीक्षकों एवं उप निरीक्षकों के लिए फाउंडेशन कोर्स संचालित किया जाता है।

नन्हें पौधों के साथ भैया-बहनों को दी गई भावभीनी विदाई, पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश

संवाददाता

बनखेड़ी/नर्मदापुरम। सरस्वती शिशु मंदिर ईशरपुर में शिक्षा सत्र के समापन पर कक्षा पांचवीं के विद्यार्थियों के लिए विदाई समारोह का आत्मीय आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्था के प्रधानाचार्य अर्जुन सिंह कुशवाहा ने की। कार्यक्रम में संस्था के पूर्व आचार्य गोविंद पटैल विशेष अतिथि के रूप में और पूर्व आचार्य मकरन सिंह कुशवाहा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। विदाई समारोह की शुरुआत मां सरस्वती के पूजन-अर्चन के साथ हुई। इस अवसर पर एक अनूठी पहल करते हुए विद्यार्थियों ने विशेष अतिथि पूर्व आचार्य गोविंद पटैल के जन्मदिन पर उन्हें पौधा भेंट कर शुभकामनाएं प्रेषित कीं। अतिथियों ने अपने उद्बोधन में छात्र-छात्राओं को उज्ज्वल भविष्य का आशीर्वाद देते हुए कहा कि अनुशासन ही विद्यार्थी जीवन की असली पूंजी है। उन्होंने बच्चों को आगामी कक्षाओं में भी इसी संस्कार और अनुशासन के साथ अध्ययन करने की सीख दी। कार्यक्रम के दौरान पर्यावरण संरक्षण के महत्व पर प्रकाश डालते हुए अंतिम कक्षा के सभी भैया-बहनों को स्मृति स्वरूप पौधे भेंट किए गए, ताकि वे अपने जीवन में शिक्षा के साथ-साथ प्रकृति की रक्षा का संकल्प भी लेकर जाएं। कार्यक्रम का सफल संचालन पूर्व आचार्य लीलाधर कुशवाहा ने किया। इस गरिमामयी अवसर पर आचार्य शैलेन्द्र राजपूत, श्रीमती रंजना राजपूत, बृजेश कुशवाहा, श्रीमती शान्ति कुशवाहा, श्रीमती हेमलता सोनी सहित बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

दर्दनाक हादसा 7 गूंज सिंगरौली की पत्रिका करंट की चपेट में आने से मासूम बच्ची की दर्दनाक मौत

गूंज सिंगरौली की पत्रिका
कार्यालय बरगवां

रिलायंस अमलोरी क्षेत्र की बस्ती में हादसा, बिजली व्यवस्था पर उठे सवाल सिंगरौली। जिले के रिलायंस अमलोरी क्षेत्र स्थित एक बस्ती में करंट लगने से एक मासूम बच्ची की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई और परिजनों में कोहराम मच गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार, बस्ती निवासी हृदय लाल कहार की पुत्री अंशिका कहार खेलते समय अचानक बिजली के करंट की चपेट में आ गई। परिजन उसे तत्काल नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे, लेकिन चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, बस्ती में खुले पड़े बिजली तार या करंट प्रवाहित हो रहे किसी उपकरण की वजह से हादसा हुआ होने की आशंका जताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग बड़ी संख्या में मौके पर एकत्र हो गए। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बिजली विभाग की टीम को भी सूचित किया गया है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि करंट कैसे फैला और लापरवाही किस स्तर पर हुई। मासूम की असमय मौत से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। क्षेत्रवासियों ने बिजली व्यवस्था दुरुस्त करने, खुले तारों को सुरक्षित करने और नियमित निरीक्षण की मांग की है, ताकि भविष्य में इस तरह की दुखद घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

गोरबी में अवैध शराब का जाल कामधेनु एसोसियेशन पर खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ाने के आरोप

गूंज सिंगरौली की पत्रिका
कार्यालय बरगवां सिंगरौली

सिंगरौली जिले के गोरबी चौकी क्षेत्र में अवैध शराब के कारोबार को लेकर हालात दिन-ब-दिन गंभीर होते जा रहे हैं। स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि शराब ठेकेदार कामधेनु एसोसियेशन द्वारा नियमों की अनदेखी करते हुए कंपोजिट शराब दुकान के सामने खुलेआम शराब पिलाई जा रही है। प्रतिबंध के बावजूद दुकान के बाहर बैठने की व्यवस्था कराए जाने से क्षेत्र में अव्यवस्था और असामाजिक गतिविधियों को बढ़ावा मिल रहा है।

अधिकारियों को खुली चुनौती?

स्थानीय लोगों का कहना है कि संबंधित विभागों को कई बार शिकायतें दी गईं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नजर नहीं आई। इससे यह सवाल उठ रहा है कि क्या ठेकेदार प्रशासन को खुली चुनौती दे रहा है? पुलिस और आबकारी विभाग की निष्क्रियता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं।

महिलाओं की सुरक्षा पर संकट

गोरबी बाजार क्षेत्र में सब्जी की दुकानों के समीप शराबियों का सुबह से ही जमावड़ा लग जाता है। आरोप है कि नशे में धुत्त कुछ लोग आने-जाने वाली महिलाओं पर अभद्र टिप्पणियां करते हैं, जिससे क्षेत्र का माहौल खराब हो रहा है। स्थानीय व्यापारियों और महिलाओं में इस स्थिति को लेकर गहरा आक्रोश है।

राजस्व हानि और सामाजिक असर

अवैध शराब बिक्री से शासन को राजस्व की क्षति होने की आशंका जताई जा रही है। साथ ही, युवाओं में बढ़ते नशे की प्रवृत्ति को लेकर भी चिंता व्यक्त की जा रही है। नागरिकों का कहना है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो स्थिति और विकट हो सकती है।

जनता ने उठाई आवाज

क्षेत्र के निवासियों ने अवैध शराब के खिलाफ एकजुट होकर सख्त कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि शासन की मंशा के विपरीत चल रही गतिविधियों पर तत्काल अंकुश लगाया जाए और जिम्मेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। अब देखना होगा कि संबंधित विभाग इस मामले में क्या कदम उठाते हैं और क्या गोरबी क्षेत्र को अवैध शराब के बढ़ते जाल से मुक्ति मिल पाती है या नहीं।

रैक से जा रहा मिलावटी कोयला! उद्योगों पर संकट, रेलवे और सरकार तक पहुंची शिकायत

गोरबी महदईया में भस्सी माफिया बेलगाम, अब सीधे मुख्यमंत्री और कोयला मंत्री को भेजी गई पूरी रिपोर्ट

गूंज सिंगरौली की पत्रिका

सिंगरौली। ऊर्जा नगरी सिंगरौली में मिलावटी कोयले का काला खेल अब नए और खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। गोरबी महदईया क्षेत्र में कोयले में भस्सी मिलाने का अवैध कारोबार सिर्फ स्थानीय सप्लाई तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अब रैक के माध्यम से बड़े उद्योगों तक पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक, महदईया रेलवे साइडिंग से रैक के जरिए कोयला बाहर भेजा जा रहा है। यदि उसमें भस्सी की मिक्सिंग की पुष्टि होती है, तो इससे उद्योगों को भारी आर्थिक नुकसान और मशीनरी को गंभीर क्षति हो सकती है। यह मामला सिर्फ राजस्व हानि नहीं, बल्कि औद्योगिक सुरक्षा और गुणवत्ता से जुड़ा बड़ा खतरा बनता जा रहा है।

त्रिमूला कंपनी की भस्सी, रेलवे साइडिंग में मिक्सिंग

गोदवाली स्थित त्रिमूला कंपनी से भस्सी लाकर कोयले में मिलाने के आरोप लगातार गहराते जा रहे हैं। निर्माण स्थल की आड़ में डंप की जा रही भस्सी को बाद में कोयले के साथ मिक्स कर बाजार में उतारा जा रहा है।

स्थानीय सूत्रों का दावा है कि

महदईया रेलवे साइडिंग पर खुलेआम मिक्सिंग का खेल चल रहा है, जबकि जिम्मेदार अधिकारी कुंभकरणी नींद में लीन नजर आ रहे हैं।

रैक से बाहर जा रहा मिलावटी माल, उद्योगों पर मंडराया संकट

रैक के माध्यम से जब यह कोयला विभिन्न उद्योगों तक पहुंचता है, तो वहां गुणवत्ता में गिरावट के कारण उत्पादन प्रभावित हो सकता है। मशीनों में तकनीकी खराबी, बॉयलर डैमेज और ऊर्जा उत्पादन में कमी जैसे गंभीर परिणाम सामने आ सकते हैं। अगर यह सिलसिला नहीं रुका, तो यह मामला सिर्फ स्थानीय स्तर का नहीं रहेगा, बल्कि प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा औद्योगिक विवाद बन सकता है।

रेलवे विभाग और सरकार तक पहुंची शिकायत

इस पूरे मामले को लेकर गूंज सिंगरौली की पत्रिका ने खबर को प्राथमिकता देते हुए संबंधित दस्तावेजों और तथ्यों के साथ रेलवे विभाग को ईमेल भेजा है। साथ ही प्रदेश के मुखिया मोहन यादव और केंद्रीय कोयला मंत्री को भी ट्विटर और ईमेल के माध्यम से शिकायत प्रेषित की गई है। पत्रिका की पहल के बाद अब भस्सी माफियाओं की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। सूत्रों का कहना है कि उच्च स्तर से जांच के संकेत मिल रहे हैं।

आखिर किसके संरक्षण में चल रहा खेल?

स्थानीय जनता सवाल उठा रही है कि जब खुलेआम रैक के जरिए कोयला भेजा जा रहा है, तो क्या गुणवत्ता जांच की प्रक्रिया सिर्फ कागजों तक सीमित है? क्या जिम्मेदार अधिकारी जानबूझकर चुप हैं, या फिर इस नेटवर्क को किसी बड़े संरक्षण का आशीर्वाद प्राप्त है?

बड़ा खुलासा जल्द!

सूत्रों का दावा है कि इस काले कारोबार से जुड़े कुछ प्रभावशाली नाम जल्द सामने आ सकते हैं। यदि निष्पक्ष जांच हुई, तो यह सिंगरौली का अब तक का सबसे बड़ा कोयला मिलावट घोटाला साबित हो सकता है।

शेष अगले अंक में

महान नदी में रेत माफियाओं का तांडव

बीच धारा में मशीनों से अवैध उत्खनन, एनजीटी नियमों को खुली चुनौती

खनिज विभाग की चुप्पी पर उठे गंभीर सवाल

गूंज सिंगरौली की पत्रिका
कार्यालय बरगवां सिंगरौली

सिंगरौली। जिले में अवैध रेत उत्खनन का खेल अब खुलेआम कानून को चुनौती देता नजर आ रहा है। देवसर तहसील अंतर्गत कारी रेत खदान में इन दिनों माफियाओं का दबदबा चरम पर बताया जा रहा है। आरोप है कि खदान का संचालन कर रही सहकार ग्लोबल लिमिटेड द्वारा स्वीकृत क्षेत्र से बाहर बड़े पैमाने पर रेत निकासी की जा रही है। स्थानीय सूत्रों का दावा है कि खदान क्षेत्र के सीमांकन चिन्ह तक मिटा दिए गए हैं, जिससे यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा कि वैध खनन क्षेत्र कहां तक है। इस स्थिति का फायदा उठाकर अलग-अलग स्थानों पर मनमाने ढंग से उत्खनन किया जा रहा है, जो सीधे तौर पर खनन नियमों का उल्लंघन है।

बीच धारा में मशीनों का कहर

सबसे गंभीर आरोप यह है कि महान नदी की मुख्य जलधारा में भारी पोकलेन और जेसीबी मशीनें उतारकर रेत निकाली जा रही है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के दिशा-निर्देशों के अनुसार नदी की सक्रिय जलधारा में मशीनों से खनन पूर्णतः प्रतिबंधित है, ताकि नदी का प्राकृतिक संतुलन और जलीय जीवन सुरक्षित रहे। इसके बावजूद नियमों की अनदेखी कर खुलेआम उत्खनन किया जाना पर्यावरणीय मानकों पर सीधा प्रहार माना जा रहा है।

नदी का स्वरूप बिगड़ने का खतरा

स्थानीय ग्रामीणों और पर्यावरण प्रेमियों का कहना है कि अंधाधुंध खनन से नदी का प्रवाह प्रभावित हो रहा है। इससे जलीय जीव-जंतुओं के अस्तित्व पर खतरा मंडरा सकता है। यदि स्थिति पर समय रहते नियंत्रण नहीं पाया गया, तो आने वाले वर्षों में नदी के पारिस्थितिक संतुलन को गंभीर नुकसान हो सकता है।

खनिज विभाग और प्रशासन पर सवाल

इतने गंभीर आरोपों के बावजूद खनिज विभाग और स्थानीय प्रशासन की चुप्पी चर्चा का विषय बनी हुई है। ग्रामीणों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच, खदान क्षेत्र के पुनः सीमांकन और अवैध उत्खनन पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। अब देखना यह है कि संबंधित विभाग इन आरोपों की जांच कर सख्त कार्रवाई करता है या नहीं।

शेष अगले अंक में

क्या हमारी ऊर्जा नगरी अपराध और नशे के अंधेरे में डूबती जा रही है

हे भगवान! किसकी बुरी नजर लग गई हमारे सिंगरौली को

गूंज सिंगरौली की पत्रिका
लेखक एवं प्रधान संपादक
लाले विश्वकर्मा

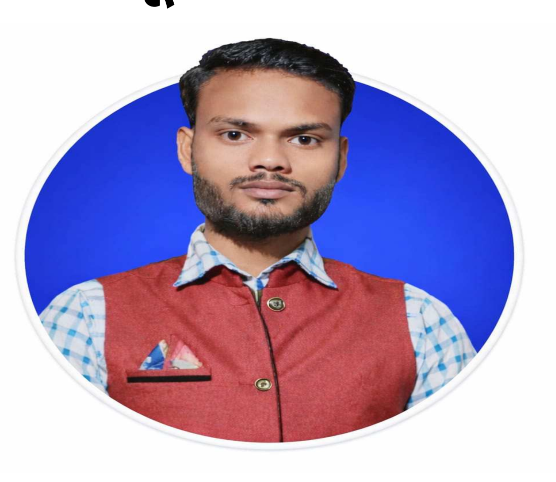

कभी मेहनत, ईमानदारी और विकास की मिसाल रहा सिंगरौली आज बेचैनी के दौर से गुजर रहा है। जिस धरती ने देश को रोशनी दी, वही धरती अब खुद अंधेरे साए से घिरती दिखाई दे रही है। गलियों में फुसफुसाहट है, चौक-चौराहों पर चिंता है, और हर घर के भीतर एक ही सवाल – आखिर किसकी बुरी नजर लग गई हमारे सिंगरौली को? नशे का फैलता जाल, बढ़ती आपराधिक गतिविधियां और कानून के डर का कम होता असर – ये केवल खबरों की सुर्खियां नहीं, बल्कि समाज के सीने पर लगते घाव हैं। सबसे पीड़ादायक सच यह है कि इस जाल में हमारे युवा फंसते जा रहे हैं। जिन हाथों में कलम और किताब होनी चाहिए थी, वे भटकाव के अंधे रास्तों की ओर बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। क्या हम चुप रहेंगे? क्या हम इंतजार करेंगे कि हालात और भयावह हो जाएं? पुलिस प्रशासन समय-समय पर कार्रवाई करता है, अभियान चलाता है, गिरफ्तारियां भी होती हैं। लेकिन यदि अपराध बार-बार सिर उठाता है, तो यह संकेत है कि अब और अधिक सख्ती, रणनीति और निरंतर निगरानी की आवश्यकता है। जनता अब औपचारिकता नहीं, बल्कि निर्णायक और दिखाई देने वाली कार्रवाई चाहती है – ऐसी कार्रवाई जिससे अपराध की जड़ें हिल जाएं। यह समय आधे-अधूरे प्रयासों का नहीं है। यह समय है स्पष्ट संदेश देने का – सिंगरौली की शांति से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। कानून का राज सिर्फ कागजों पर नहीं, जमीनी हकीकत में दिखना चाहिए। लेकिन यह लड़ाई केवल पुलिस या प्रशासन की नहीं है। समाज को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। यदि हम गलत को देखकर भी चुप रहते हैं, तो कहीं न कहीं हम भी दोषी हैं। अभिभावकों को सजग रहना होगा, शिक्षकों को मार्गदर्शन देना होगा और युवाओं को स्वयं यह निर्णय लेना होगा कि वे रोशनी का रास्ता चुनेंगे या अंधेरे का। सिंगरौली की पहचान अपराध नहीं, विकास है। यह धरती संघर्ष, श्रम और सपनों की है – न कि नशे और भय की। यदि समय रहते हम नहीं चेते, तो आने वाली पीढ़ियां हमसे सवाल करेंगी। अब वक्त है जागने का। अब वक्त है सख्ती का। अब वक्त है अपने सिंगरौली को बचाने का।

गूंज सिंगरौली की पत्रिका - जनचेतना और जनहित के लिए समर्पित)

बरगवां थाना क्षेत्र में युवक पर जानलेवा हमला

घुटने पर धारदार वार, हालत गंभीर जिला अस्पताल से जबलपुर रेफर ;घटनास्थल के पास मिला हिरण का शव, साजिश या शिकार? पुलिस जांच तेज

गूंज सिंगरौली की पत्रिका
कार्यालय बरगवां

सिंगरौली। जिले के बरगवां थाना क्षेत्र अंतर्गत पोइरा गांव में शनिवार सुबह एक सनसनीखेज और रहस्यमयी घटना सामने आई। अज्ञात हमलावरों ने युवक संदीप यादव पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। हमले में युवक के घुटने पर गहरा वार किया गया, जिससे उसका घुटना लगभग आधा कट गया। इसके अलावा शरीर के कुछ हिस्सों में झुलसने के निशान भी पाए गए हैं, जिससे वारदात को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार, सुबह करीब 7 बजे ग्रामीणों ने युवक को लहूलुहान अवस्था में देखा और तत्काल पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही बरगवां थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को जिला मुख्यालय स्थित ट्रामा सेंटर पहुंचाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद हालत नाजुक देखते हुए चिकित्सकों ने उसे बेहतर इलाज के लिए जबलपुर रेफर कर दिया। घटना को और रहस्यमयी बनाते हुए घटनास्थल से लगभग 100 मीटर की दूरी पर एक हिरण का शव भी बरामद हुआ है। इस मामले में वन विभाग ने भी संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है। बरगवां थाना प्रभारी निरीक्षक मो. समीर के अनुसार, अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और सभी संभावित पहलुओं – पुरानी रंजिश, आपराधिक साजिश या वन्यजीव शिकार – को ध्यान में रखते हुए जांच की जा रही है। फिलहाल युवक की स्थिति गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा और दोषियों को कानून के कठघरे में खड़ा किया जाएगा।

ट्रैफिक बेपटरी,जाम से पस्त जिला;वसूली मस्त तंत्र

एसी में बैठे साहब, मैदान में सेटिंग का खेल – क्या कप्तान के गले की हड्डी बन रहे ट्रैफिक प्रभारी

गूंज सिंगरौली की पत्रिका
कार्यालय, बरगवां

सिंगरौली जिले की ट्रैफिक व्यवस्था इन दिनों पूरी तरह सवालों के घेरे में है। शहर से लेकर ग्रामीण अंचलों तक जाम अब ÷अपवाद÷ नहीं बल्कि ÷रोज़मर्रा की हकीकत÷ बन चुका है। मुख्य बाजार, औद्योगिक क्षेत्र और प्रमुख चौराहों पर घंटों वाहनों की लंबी कतारें लगी रहती हैं। आम नागरिक, छात्र, कर्मचारी और व्यापारी–सभी इस अव्यवस्था से त्रस्त हैं। लेकिन मामला केवल जाम तक सीमित नहीं है। चेकिंग अभियान, कथित वसूली और ओवरलोड वाहनों की बेरोकटोक आवाजाही को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है।

थाने के सामने से गुजरती ओवरलोड गाड़ियां

स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्रतिदिन ओवरलोड वाहन थाना परिसर के सामने से गुजर रहे हैं। सवाल उठ रहा है– यदि ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन कराया जा रहा है, तो इन भारी वाहनों पर कार्रवाई क्यों नहीं दिखती? छोटे वाहन चालकों पर कड़ी चेकिंग और भारी वाहनों पर कथित नरमी–यह विरोधाभास लोगों के मन में संदेह पैदा कर रहा है। जनता पूछ रही है कि क्या नियम सबके लिए समान हैं या फिर सेटिंग के हिसाब से लागू हो रहे हैं?

बरगवां से जयंत

तक सक्रिय तंत्र

बरगवां, देवसर, सरई, लगाडोल, नवानगर, मोरवा और जयंत तक लगातार वाहन रोककर जांच की जा रही है। कई वाहन चालकों का कहना है कि जिले में एक संगठित नेटवर्क सक्रिय है, जो व्यापक स्तर पर चेकिंग अभियान चला रहा है। हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन लगातार मिल रही शिकायतों ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्नचिह्न खड़े कर दिए हैं।

मुआवजे के आरोप और तबादले की कहानी

शहर में यह चर्चा भी है कि संबंधित अधिकारी पर पूर्व में मुआवजे के मामलों को लेकर सवाल उठे थे। उस समय तत्कालीन विधायक रामलल्लू वैश्य ने डीजीपी को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की थी। शिकायत के बाद उनका तबादला भी हुआ था। अब सवाल यह उठ रहा है कि यदि पहले गंभीर शिकायतों के आधार पर हटाया गया था, तो फिर दोबारा वापसी किन परिस्थितियों में हुई? राजनीतिक हलकों में यह चर्चा भी है कि वर्तमान विधायक रामनिवास शाह ने आखिर किन परिस्थितियों में उन्हें पुनः स्वीकार किया? क्या यह महज प्रशासनिक निर्णय था या इसके पीछे कोई राजनीतिक समीकरण?

जाम में पिसती जनता, जिम्मेदारी किसकी?

मुख्य बाजारों में घंटों जाम लगा रहता है। एम्बुलेंस तक फंस जाती हैं। स्कूल बसें देर से पहुंचती हैं। छोटे व्यापारी आर्थिक नुकसान झेल रहे हैं। लोगों का कहना है कि ट्रैफिक नियंत्रण के लिए कोई ठोस और दीर्घकालिक योजना नजर नहीं आती। मौके पर समन्वय की कमी साफ दिखाई देती है। यदि व्यवस्था इतनी बिगड़ी हुई है, तो वरिष्ठ अधिकारी स्वयं सड़कों पर उतरकर स्थिति का निरीक्षण क्यों नहीं करते? पूरे मामले में पुलिस पक्ष जानने के लिए संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन संबंधित थाना प्रभारी से बात नहीं हो सकी। फोन रिसीव न होने से पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर और सवाल खड़े हो गए हैं। संवाद का रास्ता बंद होगा तो अफवाहों को जगह मिलेगी और अविश्वास बढ़ेगा।

जनता के सीधे सवाल

ओवरलोड वाहन थाने के सामने से कैसे गुजर रहे हैं पूरे जिले में चल रहे चेकिंग अभियान का स्पष्ट लिखित आदेश क्या है? पूर्व शिकायत और तबादले के बाद वापसी किन परिस्थितियों में हुई? क्या ट्रैफिक सुधार की कोई ठोस और पारदर्शी योजना है? सिंगरौली की जनता अब केवल जाम से राहत नहीं, बल्कि जवाबदेही और पारदर्शिता चाहती है। यदि समय रहते प्रशासन ने स्थिति स्पष्ट नहीं की और प्रभावी कदम नहीं उठाए, तो यह मुद्दा केवल ट्रैफिक अव्यवस्था तक सीमित नहीं रहेगा–बल्कि व्यापक जनआक्रोश का कारण बन सकता है।

स्वामी मुद्रक प्रकाशक लाले प्रसाद विश्वकर्मा द्वारा सिया ग्राफिक्स और प्रिंटर्स प्लॉट नं. 15, खसरा नं. 602, त्रिवेणी कुंज, बोदला, आगरा, उत्तर प्रदेश - 282007 से मुद्रित एवं 51-1, पड़री, गोदवाली पोस्ट ऑफिस, गोरबी, सिंगरौली, मध्य प्रदेश - 486892 से प्रकाशित। संपादक- लाले प्रसाद विश्वकर्मा (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र सिंगरौली न्यायालय रहेगा) PRGI MPHIN/26/A0876 Phone 6261729146 Email: goonjsingrauliki@gmail.com